संयम ◆ संस्कार ◆ संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

शहर समता

वर्ष-22 अंक- 145
पृष्ठ 8
शुक्रवार
13 फरवरी 2026
प्रात: संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

प्रयागराज से प्रकाशित   Email : shaharsamta@gmail.com   Website : https://Shaharsamta.com   सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- डायबिटीज रोगियों को भूलकर भी...   विचार- मोदी जी, कृपया कभी तो...   खेल- 15 फरवरी को आमने-सामने होंगे...

प्रधानमंत्री मोदी ने सीतारमण के बजट के व्यापक रोडमैप को सराहा, बोले-

अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई दिशा

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वित्त मंत्री का भाषण साझा करते हुए जरूरी चीजों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में रिफॉर्म एक्सप्रेस, एमएसएमई को समर्थन, कौशल विकास, नई पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे अहम पहलुओं को विस्तार से रखा है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि बजट 2026–27 में राज्यों को करों में हिस्सेदारी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कुल 25.44 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने का अनुमान है। यह राशि 2025–26 की तुलना में 2.7 लाख करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण कम किया गया है। बजट 2026–27 में कुल 17.15 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश का प्रावधान किया गया है, जिसे उन्होंने 4 गुना गुणक प्रभाव वाला बताया। केंद्र का प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय 12.22 लाख करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है और पिछले वर्ष की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक है। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तांतरण जोड़ने के बाद कुल पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.4 प्रतिशत बैठता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे यह आरोप गलत साबित होता है कि राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रखने के लिए विकास व्यय घटाया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं सभी राज्यों के लिए खुली हैं। राज्य अगर व्यवहार्य प्रस्ताव लेकर आते हैं तो पीएम गति शक्ति के मानकों के तहत मेगा फूड पार्क, आईटी पार्क, स्मार्ट सिटी, जलमार्ग, एलाइड एंड हेल्थ सर्विस हब जैसे प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा और उपचार सुविधाओं को एक ही परिसर में विकसित कर भारत को मेडिकल टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। युवाओं के लिए शिक्षा और स्किलिंग को एकीकृत करने वाले मेगा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें औद्योगिक क्लस्टर के पास विकसित किया जा सकता है। इनका उद्देश्य छात्रों को उद्यमिता के लिए तैयार करना है।

दिल्ली में कल गुणवत्ता आश्वासन उद्योग सम्मेलन

जहाज निर्माण और रक्षा उपकरण में गुणवत्ता पर होगा मंथन

नई दिल्ली,एजेंसी। नई दिल्ली में कल यानी 13 फरवरी को एक अहम क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय और उद्योग जगत के बड़े अधिकारी मिलकर जहाज निर्माण और संबंधित उपकरणों की भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। रक्षा निर्माण में आज गुणवत्ता सिर्फ तकनीकी जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बन चुकी है। युद्धपोत हों, कॉम्बैट सिस्टम हों या स्पेयर पार्ट्स, हर उपकरण की विश्वसनीयता सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि हर जहाज और उपकरण उच्च गुणवत्ता वाला हो। कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में होगा। इसकी थीम है 'ट्रेसबिलिटी, स्पीड और ट्रस्टश टेक्नोलॉजी के जरिए स्मार्ट क्वालिटी एश्योरेंस'। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय, नौसेना, शिपयार्ड, रक्षा पीएसयू और निजी कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे। उद्देश्य है रक्षा निर्माण में गुणवत्ता की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना। इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ सामान बनाना काफी नहीं है। हर पार्ट की पूरी जानकारी होना जरूरी है, यह कहां बना, कैसे बना और किस स्टेज पर जांच हुई। डिजिटल तकनीक से इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जा सकता है। कॉन्क्लेव में यह भी चर्चा होगी कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से मंजूरी और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए और इंडस्ट्री और नौसेना के बीच भरोसा मजबूत किया जाए। 'इंडियन नेवल एंड मरीन इंडस्ट्री–ए कैपेबिलिटी कैटलॉग' जारी होगा, जिससे इंडस्ट्री की क्षमता एक जगह देखी जा सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को लगाई कड़ी फटकार, कहा-

वह सिर्फ दिवालिया बिल्डरों के लिए काम करता है

नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह संस्था दिवालिया होने वाले बिल्डरों की मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है और अब समय आ गया है कि सभी राज्य इसके गठन पर दोबारा विचार करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जिन लोगों के हितों की रक्षा के लिए रेरा बनाया गया था, वे पूरी तरह उदास, निराश और हताश हैं और उन्हें कोई प्रभावी राहत नहीं मिल रही। कोर्ट ने यहां तक कहा कि यदि इस संस्था को समाप्त भी कर दिया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि शिमला में भीड़ कम करने और प्रशासनिक कारणों से कार्यालय स्थानांतरण का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने पीठ को बताया कि सरकार रेरा को धर्मशाला शिफ्ट करना चाहती है। विरोधी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि रेरा के लगभग 90 प्रतिशत प्रोजेक्ट और 92 प्रतिशत लंबित शिकायतें शिमला, सोलन, परवाणू और सिरमौर जिलों से संबंधित हैं, जो 40 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जबकि धर्मशाला में केवल 20 प्रोजेक्ट हैं। सुनवाई के दौरान जब पीठ को बताया गया कि रेरा में एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है, तो मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कई राज्यों में ऐसी संस्थाएं रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गई हैं। याचिका पर नोटिस जारी करते हुए, बेंच ने कहा, राज्य को रेरा का ऑफिस अपनी पसंद की जगह पर शिफ्ट करने की इजाजत है। हालांकि, यह हाईकोर्ट में पेंडिंग रिट पिटीशन के आखिरी नतीजे पर निर्भर करेगा। हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने बेंच को बताया कि एक पॉलिसी फैसले के मुताबिक, राज्य पालमपुर, धर्मशाला और दूसरे शहरों को डेवलप कर रहा है। सीजेआई ने पूछा, ष्एक सेवानिवृत्त अधिकारी को रखने का क्या लॉजिक है? वह पालमपुर को विकसित करने में कैसे मदद कर पाएगा।

अमेरिकी फैक्टशीट में संशोधन साझा सहमति के अनुरूप

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। अमेरिका द्वारा जारी संशोधित इंडिया–यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क फैक्टशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी दस्तावेज में किए गए बदलाव दोनों देशों के बीच बनी साझा समझ के अनुरूप हैं। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका ने पारस्परिक तथा परस्पर लाभकारी व्यापार के लिए एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया था। यही संयुक्त वक्तव्य इस पूरी प्रक्रिया का आधार है और दोनों पक्षों की आपसी सहमति को दर्शाता है। प्रवक्ता के अनुसार, अमेरिकी फैक्टशीट में जो संशोधन किए गए हैं, वे उसी संयुक्त वक्तव्य में शामिल बिंदुओं और सहमतियों को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने दोहराया कि दोनों देश अब इस तय ढांचे को लागू करने और अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में मिलकर काम करेंगे।

बांग्लादेश में चुनावों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव के परिणामों का इंतजार करना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि जनता का जनादेश किस प्रकार का आया है, उसके बाद ही संबंधित मुद्दों पर आगे विचार किया जाएगा। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा जहां तक चुनाव की प्रक्रिया का सवाल है, हमारा रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है। हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और भरोसेमंद चुनाव के पक्ष में हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता को महत्व देता है और दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर स्थिति की निगरानी जारी रखेगा। रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता वाले कथित वीडियो को नहीं देखा है। उन्होंने बताया यदि ऐसा कोई वीडियो मौजूद है, चाहे वह सच हो या झूठ, हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता ने हरदीप सिंह पुरी के बयान पर कहा इस मामले में हमने पहले ही लिखित और मौखिक दोनों तरह के स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के भारत दौरा को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति लूला दिल्ली में आयोजित होने वाले दूसरे एआई समिट (19–20 फरवरी) में भाग लेंगे। यह समिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और नीतिगत समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ब्राजील के राजकीय दौरे का मुख्य दिन 21 फरवरी होगा। इसी दिन भारत और ब्राजील के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति लूला की मेजबानी भारत की राष्ट्रपति करेंगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति समेत कई अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उनसे मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति लूला के साथ कई मंत्री और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि बिजनेस डेलीगेशन को जोड़ने के लिए अलग–अलग बैठकों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिससे भारत–ब्राजील आर्थिक साझेदारी को नई गति मिल सके।

अमेरिका के बॉर्ड ऑफ पीस (ठवंतक वि्चिमंबम) में भारत को शामिल करने के निमंत्रण पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका की ओर से यह प्रस्ताव मिला है और इसे फिलहाल भारत द्वारा गंभीरता से देखा जा रहा है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने हमेशा पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का समर्थन किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस पहल का स्वागत किया है, जो क्षेत्र में, विशेषकर गाजा में दीर्घकालिक और टिकाऊ शांति की दिशा में एक मार्ग प्रदान करती है। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत इस प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर रहा है और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका पर निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल के कनाडा के ओटावा दौरे के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनएसए ने अपने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की, जो सुरक्षा मामलों में चल रहे सहयोग और समन्वय का हिस्सा है। रणधीर जायसवाल के अनुसार, यह दौरा भारत और कनाडा के बीच नियमित सुरक्षा संवाद का हिस्सा है।

निकाय चुनाव में हार के बाद बोले-

वफादारी की दीवार को नहीं तोड़ सकता पैसा

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों में महायुति का दबदबा रहा, शिवसेना (यूबीटी) और महा विकास अघाड़ी को हार मिली। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए भाजपा पर निशाना साधा और भविष्य में मजबूती से वापसी का भरोसा जताया। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए सभी चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम के चुनावों में खुब पैसा बहाया गया इसके बाद भी ये वफादारी की दीवार नहीं तोड़ पाए।

12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों में अधिकतर पर महायुति का दबदबा रहा। इसमें से कुछ सीटों पर चुने गए शिवसेना के सदस्यों और कार्यकर्ताओं से से हिम्मत न हारने और आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार रहने को कहा। नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में लगातार जीत के बाद, भाजपा ने जीत की हैट्रिक हासिल की है, जिससे वह राज्य में नंबर वन पार्टी बन गई है। इसके उलट, महा विकास अघाड़ी को इस चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?

जानवरों से जुड़े फैसले, विशेषज्ञों को ही लेने चाहिए

नागपुर,एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को एक अलग और मजबूत वेटरिनरी काउंसिल के गठन की पैरवी की। उन्होंने कहा कि जानवरों और जनसुरक्षा से जुड़े फैसले वेटरिनरी डॉक्टरों और विषय–विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ही होने चाहिए। भागवत नागपुर में इंडियन सोसायटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ कैनाइन प्रैक्टिस (आईएसएसीपी) के 22वें वार्षिक अधिवेशन और रोल ऑफ कैनाइन इन वन हेल्थ बिल्डिंग पार्टनरशिप्स एंड रिजॉल्विंग चौलेंजेज विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इसका आयोजन आईएसएसीपी, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी (एमएएफएसयू), नागपुर और नेशनल एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड रिसर्च (एनएडब्ल्यूएआर) ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन की शुरुआत में भागवत ने कहा, मैंने इसी कॉलेज में पढ़ाई की है। हालांकि मुझे वेटरिनरी क्षेत्र छोड़े 50 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन आप लोगों जितना ज्ञान अब मेरे पास नहीं है। फिर भी पूर्व छात्र के रूप में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूं। दिल्ली में हाल ही में लावारिस कुत्तों को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि बहस दो चरम सीमाओं में बंट गई थी, श्एक पक्ष कह रहा था कि सभी कुत्तों को मार दो, दूसरा कह रहा था कि उन्हें छुओ भी मत। लेकिन अगर इंसानों को कुत्तों के साथ रहना है, तो यह सोचना होगा कि कैसे साथ रहें। उन्होंने वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान पर जोर देते हुए कहा, कुत्तों की संख्या नसबंदी के जरिए नियंत्रित की जा सकती है। इंसानों के लिए जोखिम कम करने के कई उपाय हैं। ये भावनाओं से नहीं, ज्ञान से निकले समाधान हैं। संस्थागत सुधार की मांग करते हुए भागवत ने स्पष्ट कहा, श्अलग वेटरिनरी काउंसिल होनी चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह जरूरी है। जानवरों से जुड़े फैसले उन्हीं के हाथ में होने चाहिए जो इस विषय को समझते हैं।

114 राफेल और 6 पी–8आई विमान खरीद को मंजूरी, 3.25 लाख करोड़ रुपये का है रक्षा सौदा

नई दिल्ली,एजेंसी। देश की सुरक्षा व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने एक ऐतिहासिक खरीद को मंजूरी दी है। परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों और नौसेना के लिए 6 पी–8आई पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद योजनाओं में से एक माना जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। इस सौदे का सबसे अहम पहलू वायुसेना की गिरती स्क्वाड्रन संख्या को संभालना है।

114 नए राफेल विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। वर्तमान में वायुसेना के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। डीएसी की मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) के पास भेजा जाएगा। आसमान के साथ–साथ समंदर में भी भारत की निगरानी क्षमता बढ़ने वाली है।

ट्रायल से भागने वाले आरोपी को नहीं मिल सकती धारा-256 में राहत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है तो केवल शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के आधार पर उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-256 के तहत बरी नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है तो केवल शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के आधार पर उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-256 के तहत बरी नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में बरी करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने चेक बाउंस के आरोपी राय अनूप प्रसाद की आठ याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला आगरा की एक अदालत में लंबित परिवाद (कम्प्लेंट केस) से जुड़ा है। मजिस्ट्रेट ने 29 सितंबर 2014 को शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के आधार पर धारा-256 सीआरपीसी के तहत आरोपी को बरी कर दिया था। जबकि, रिकॉर्ड से स्पष्ट था कि आरोपी कभी भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और न ही ट्रायल शुरू हुआ था। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता गोपाल प्रसाद शर्मा ने अपने परिचित राय अनूप प्रसाद से नोएडा में 80 लाख रुपये में एक फ्लैट का सौदा किया था। 30 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे। बाद में सौदा पूरा नहीं हो सका। आरोपी ने रकम लौटाने के लिए आठ चेक दिए, लेकिन सभी बाउंस हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में परिवाद दायर किया।

हाईकोर्ट पानी टंकी आरओबी और शास्त्री ब्रिज के समानांतर पुल व राम सेतु के शुरू होने की संभावना

प्रयागराज। प्रदेश के बजट से जिले में कई पुल, फ्लाईओवर और रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के शुरू होने की संभावना है। इनमें तीन नए यमुना-गंगा पुल, तीन रेलवे ओवरब्रिज/फ्लाईओवर के निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के बजट से जिले में कई पुल, फ्लाईओवर और रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के शुरू होने की संभावना है। इनमें तीन नए यमुना-गंगा पुल, तीन रेलवे ओवरब्रिज/फ्लाईओवर के निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।

प्रमुख योजना में 500 करोड़ की लागत से करेलाबाग-मकोड़ा

पुल, शास्त्री ब्रिज (गंगा पुल) के समानांतर लगभग 2.3 किमी लंबा एक नया फोर लेन पुल बनेगा। यह दारागंज/सलोरी से झूंसी को जोड़ेगा। इस परियोजना की लागत 850 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है और इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, यमुना नदी पर सलोरी से हेतापट्टी तक पुल बनना है। इसके बजट की पहली किस्त जारी हो चुकी है।

वहीं, पुराने शहर से नए शहर को जोड़ने वाला हाईकोर्ट रेलवे पुल का भी निर्माण होना है। इसके लिए जर्जर हो चुके पुराने रेलवे पुल को ध्वस्त कर इसी जगह पर करीब 80 करोड़ की लागत से 573 मीटर लंबा आरओबी तैयार किया जाएगा। हाईकोर्ट आरओबी सहित कई सड़कों, फ्लाईओवर, सेतु के निर्माण की कार्य योजना लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तैयार कर चुका है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उधर, यमुना नदी पर लगभग 258-400 करोड़ की लागत से 1200 मीटर लंबा और पांच मीटर चौड़ा एक आधुनिक राम सेतु पैदल पुल बनाने की योजना है। यह पुल मिंटो पार्क से अरैल के शिवालय पार्क तक जुड़ेगा। पुल चार साल में बनेगा। ऐसे में अगर बजट मिलता है, तो इन सभी का निर्माण इसी वर्ष शुरू होने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और उनकी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सरकार से मांगा प्लान

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत कार्ययोजना पर जवाब तलब किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत कार्ययोजना पर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी 80 वर्षीय वृद्ध गुलाब कली की याचिका पर दिया है। याची बीमार है और अपनी दो पोतियों के साथ अकेले रह रही है। उसकी एक पोती दिव्यांग है। ऐसे में वृद्धा ने आशंका जताई थी कि कुछ दबंग उसकी पैतृक आबादी वाली जमीन पर अवैध कब्जा करने और उसे बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए अभी तक विशेष ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) का गठन नहीं किया गया है।अधिनियम की धारा 22(2) के तहत राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे। नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना डीएम की जिम्मेदारी है। इस पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उन्होंने अधिनियम की धारा-22(2) के तहत अनिवार्य एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और डीएम वृद्धों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि यह दो निजी पक्षों के बीच का विवाद लग सकता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति पर कब्जे के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस विशेष कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थायी दिशानिर्देश तय करना आवश्यक है।

जमीन के विवाद में बहन-भाई से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

प्रयागराज। जमीन के विवाद में भाई-बहन से मारपीट की गई। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होलागढ़ के बृंसिहपुर रामगढ़ निवासी विकास पटेल ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर विपक्षियों ने लाठी-डंडे से घर में घुसकर उसे और उसकी बहनों सीमा एवं आशा से मारपीट की।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- पीठ थपथपाने व महिमामंडन के लिए गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा सकती पुलिस

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पीठ थपथपाने व महिमामंडन के लिए पुलिस किसी नागरिक पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं कर सकती। यह एक्ट सामान्य धाराओं की अपग्रेडेड कॉपी नहीं है, जिसे हर मामले में लगा दिया जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पीठ थपथपाने व महिमामंडन के लिए पुलिस किसी नागरिक पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं कर सकती। यह एक्ट सामान्य धाराओं की अपग्रेडेड कॉपी नहीं है, जिसे हर मामले में लगा दिया जाए। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने बस्ती निवासी उस्मान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

साथ ही विवेचक और थाना प्रभारी से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि केवल पुलिस की छवि सुधारने या आंकड़े बेहतर दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित करना कानून की मंशा के विपरीत है। गैंगस्टर एक्ट अत्यंत कठोर कानून है, जिसका प्रयोग सोच-समझकर और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यही कारण है कि गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है, जिसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने याची पर पहले से दर्ज एक केस के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर दिया था। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पूर्व में दर्ज मुकदमे में याची जमानत पर है। इसके बावजूद पुलिस ने केवल अपने आंकड़ों को सुधारने और उपलब्धियां दिखाने के उद्देश्य से उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। एफआईआर दर्ज करने से पहले गैंगस्टर एक्ट के अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया गया और यह कार्रवाई पूरी तरह दुर्भावना से प्रेरित है।

स्वेच्छा से समझौता तो रद्द किया जा सकता है एससी-एसटी का मुकदमा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामला मूलरूप से निजी विवाद का हो, अपराध जाति के आधार पर न किया गया हो और पक्षकारों के बीच समझौता स्वेच्छा से हो तो एससी/एसटी एक्ट की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामला मूलरूप से निजी विवाद का हो, अपराध जाति के आधार पर न किया गया हो और पक्षकारों के बीच समझौता स्वेच्छा से हो तो एससी/एसटी एक्ट की कार्यवाही रद्द की जा सकती है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम की एकल पीठ ने अखिलेश श्रीवास्तव की याचिका स्वीकार कर ली।

झांसी के सिपरी बाजार थाने में अखिलेश के खिलाफ धोखाधड़ी व चोट पहुंचाने समेत एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 2016 में आरोपपत्र दाखिल हुआ और झांसी के एसीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया। मामला विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) में विचाराधीन था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि दोनों पक्षों के बीच बिना किसी दबाव या प्रलोभन के समझौता हो चुका है। इसका सत्यापन झांसी के विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट की ओर से 12 अगस्त 2025 को लिया गया था। रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि विवाद निजी प्रकृति का है और प्रथम दृष्टया यह नहीं दिखता कि कथित अपराध सूचक की जाति के कारण किया गया था। ऐसे में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले रामावतार बनाम मध्य प्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामला मूलतः निजी या सिविल प्रकृति का हो और समझौता स्वतंत्र इच्छा से हो तो कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। बशर्ते अधिनियम के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ित पक्ष ने किसी दबाव या भयवश समझौता नहीं किया है। कोर्ट ने गुलाम रसूल खान मामले का हवाला देते हुए कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत दायर आपराधिक अपील में समझौते के आधार पर कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। इसके लिए सीआरपीसी की धारा-482 का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने पुलिस की ओर से दायर 21 जनवरी 2016 की चार्जशीट और एसीजेएम कोर्ट के 27 फरवरी 2016 के संज्ञान आदेश व विशेष सत्र परीक्षण की पूरी कार्यवाही को रद्द कर अपील को समझौते के अनुसार स्वीकार कर लिया है।

अधिवक्ता कानून तोड़े तो गिरती है पेशे की गरिमा, कानपुर के वकील की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई अधिवक्ता कानून का उल्लंघन करता है तो वह विधि व्यवसाय की गरिमा को कम करता है। अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होता है और न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई अधिवक्ता कानून का उल्लंघन करता है तो वह विधि व्यवसाय की गरिमा को कम करता है। अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होता है और न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उसका पेशा उच्चतम नैतिकता, ईमानदारी और कानून के शासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित है। इसी टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने धोखाधड़ी के आरोप में नामजद कानपुर नगर निवासी अधिवक्ता आशीष शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी 12वीं की परीक्षा में असफल रहा था, जबकि उसने परीक्षा उत्तीर्ण होने का दावा किया। बोर्ड अधिकारियों की रिपोर्ट में भी उसके फेल होने का उल्लेख है। ऐसे में यह दलील कि केवल 12वीं का प्रमाणपत्र दीमक के कारण नष्ट हो गया, अविश्वसनीय प्रतीत होती है। खासकर तब जब अन्य शैक्षिक अभिलेख सुरक्षित हैं।

कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी ने अग्रिम जमानत दिए जाने के दौरान शर्तों का पालन नहीं किया, जो न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उसकी अनदेखी को दर्शाता है। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरिदमन सिंह ने आरोप लगाया है कि आशीष शुक्ला ने जाली शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कराया। इस संबंध में कानपुर नगर कोतवाली में केस दर्ज है। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे साजिशन फंसाया गया है। इससे पहले सेशन जज, कानपुर नगर ने 15 नवंबर 2025 को उसकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी।

इसी आदेश को उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया।हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निपटारे तक सीमित हैं। ट्रायल के दौरान मामले के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही ट्रायल कोर्ट को लंबित मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया।

माघ मेला: आस्था, परंपरा और पर्यावरण की साझा जिम्मेदारी

प्रयागराज। माघ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

माघ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है।

प्लास्टिक मुक्त माघ मेला की दिशा में कदम

मेले के दौरान पॉलिथीन और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसे देखते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रशासन और सरकार ने प्लास्टिक मुक्त माघ मेला के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाया है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे पॉलिथीन के बजाय पर्यावरणदृ अनुकूल विकल्प अपनाएं, ताकि संगम और आसपास का क्षेत्र स्वच्छ बना रहे।

पियर्स की अनोखी और संवेदनशील पहल

इसी दिशा में पियर्स ने एक सराहनीय और व्यावहारिक समाधान के साथ माघ मेले में भागीदारी की है। हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड के इस प्रतिष्ठित ब्रांड ने माघ मेले में स्नान के बाद कपड़े बदलने की सुविधा के लिए विशेष चेंजिंग रूम स्थापित किए हैं।

इसके साथ ही, चेंजिंग रूम के पास महिलाओं को इको-फ्रेंडली जूट बैग वितरित किए जा रहे हैं, ताकि वे अपने गीले कपड़े आसानी से और सुरक्षित तरीके से ले जा सकें। यह पहल पॉलिथीन के उपयोग को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दे रही है।

आस्था के साथ प्रकृति की सुरक्षा

पियर्स की यह सोच न केवल महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखती है, बल्कि माघ मेले को हरित और स्वच्छ बनाने की सरकारी पहल के साथ भी पूरी तरह मेल खाती है। जूट बैग जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाकर यह संदेश दिया जा रहा है कि आस्था के साथ-साथ प्रकृति की रक्षा भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

माघ मेले में पियर्स की यह पहल एक उदाहरण है कि किस तरह ब्रांड सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों को समझते हुए सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जहां श्रद्धा, सुविधा और प्रकृति तीनों का संतुलन बना रहे।

मोबाइल छीनकर भागे आरोपी को किया गिरफ्तार

प्रयागराज। थाना क्षेत्र के सड़वा नहर के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन छीनकर भागे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। कौंधियारा गांव निवासी बृजेश भारतीय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह अपने मोबाइल फोन से बातचीत कर रहा था। तभी बाइक सवार दो युवक उनके पास पहुंचे और पता पूछने के बहाने मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे। थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि बुधवार को सड़वा नहर पुलिया के पास से आरोपी रावेंद्र निषाद उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया गया।

बेटी के गौना में शामिल होंगे जेल में बंद कपिल मुनि करवरिया, हाईकोर्ट ने मंजूर की अल्पकालीन जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया बेटी के गौना रस्म में शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो दिन की अल्पकालीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया बेटी के गौना रस्म में शामिल होंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो दिन की अल्पकालीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने उनकी अर्जी पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने बताया कि 13 फरवरी को पूर्व सांसद की बेटी का गौना है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कपिल मुनि करवरिया पुलिस की निगरानी में 12 फरवरी शाम चार बजे से 14 फरवरी सुबह 11 बजे तक अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकेंगे। इसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होना होगा। अल्पकालीन जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कहा कि जेल के भीतर उनके सही इलाज न होने की शिकायत भी की। कहा कि कपिल मुनि स्पॉन्डिलाइटिस व हड्डियों की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। जेल में उन्हें उचित फिजियोथेरेपी नहीं मिल रही है। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के मुताबिक पूर्व सांसद को तत्काल बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करने का आदेश दिया है।

नेत्र संस्थान निदेशक पद पर विभागाध्यक्ष का ही अधिकार, वरिष्ठतम प्रोफेसर का नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक यह पद अलग से सृजित नहीं किया जाता, तब तक संस्थान के विभागाध्यक्ष को ही निदेशक-सह-प्रोफेसर नामित किया जाएगा, न कि वरिष्ठतम प्रोफेसर को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मनोहर दास क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में निदेशक पद के विवाद का निस्तारण कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह पद अलग से सृजित नहीं किया जाता, तब तक संस्थान के विभागाध्यक्ष को ही निदेशक-सह-प्रोफेसर नामित किया जाएगा, न कि वरिष्ठतम प्रोफेसर को। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने डॉ.अपराजिता चौधरी और डॉ.संतोष कुमार की याचिका पर दिया है। डॉ.अपराजिता ने याचिका दायर कर नेत्र संस्थान में डायरेक्टर कम प्रोफेसर के रूप में नामित किए जाने की मांग की। उनका कहना था कि वह संस्थान में सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। दूसरी ओर वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष ने दावा किया कि 1976 के शासनादेश के अनुसार विभागाध्यक्ष ही संस्थान के निदेशक होंगे। कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई 1976 का शासनादेश स्पष्ट रूप से विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर को ही निदेशक-सह-प्रोफेसर नामित करने का प्रावधान करता है। 20 अप्रैल 2010 के शासनादेश में भले ही निदेशक पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया हो, लेकिन प्रयागराज स्थित इस संस्थान में कभी भी निदेशक का पृथक पद सृजित नहीं किया गया। कोर्ट ने पाया कि डॉ. अपराजिता का नौ मई 2025 को निदेशक पद पर नामांकन तब किया गया, जब वे विभागाध्यक्ष नहीं थीं। इसे अवैध करार देते हुए कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया। साथ ही डॉ. संतोष का चार अप्रैल और 29 अगस्त 2025 को निदेशक पद पर किया गया नामांकन वैध ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि जब तक शासन स्तर से मनोहर दास क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में निदेशक का पृथक पद सृजित नहीं कर दिया जाता, तब तक संस्थान का विभागाध्यक्ष ही निदेशक-सह-प्रोफेसर पदनाम धारण करेगा।

'कानून का पालन हर व्यक्ति का परम कर्त्तव्य है, अलग से नहीं दे सकते अवैध काम न करने का आदेश'

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को अवैध काम न करने का परमादेश अदालत नहीं दे सकती। कानून का पालन करना हर व्यक्ति का परम कर्त्तव्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को अवैध काम न करने का परमादेश अदालत नहीं दे सकती। कानून का पालन करना हर व्यक्ति का परम कर्त्तव्य है। इसके लिए अलग से निर्देश देने की न जरूरत है और न ही कानून में कोई प्रावधान है। इस टिप्पणी के साथ मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने मथुरा नगर निगम क्षेत्र में ऑटो और टेंपो चालकों से कथित अवैध वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुनने से इन्कार कर दिया। ऑटो-टेंपो और थ्री-व्हीलर ड्राइवर एसोसिएशन समिति के अध्यक्ष जहीर खान की ओर से दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि मथुरा नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी (प्रतिवादी संख्या-4) के स्तर पर चालकों से अवैध रूप से शुल्क वसूला जा रहा है। लिहाजा, उन्हें अवैध वसूली रोके जाने का निर्देश जारी किया जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर स्पष्ट किया कि इस तरह की जनहित याचिका विचारणीय नहीं है। ऐसी मांग के लिए अदालत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। क्योंकि, कानून में ऐसी किसी स्थायी निषेधाज्ञा की परिकल्पना नहीं की गई है, जो केवल यह कहे कि प्रशासन अवैध गतिविधि न करे।

मामूली कहासुनी में मासूम की हत्या, फांसी पाए चाचा की जमानत खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामूली कहासुनी के दौरान आठ वर्षीय मासूम की हत्या में फांसी की सजा पाए चाचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने दीपू की जमानत अर्जी दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामूली कहासुनी के दौरान आठ वर्षीय मासूम की हत्या में फांसी की सजा पाए चाचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने दीपू की जमानत अर्जी दिया है। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र का है। आरोपी ने 23 जुलाई 2024 को मासूम काव्या की हत्या व पांच लोगों पर हमला किया था।

शहर समता विचार मंच द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सफलतापूर्वक सम्पन्न

प्रयागराज। शहर समता विचार के तत्वावधान में आयोजित गूगल मीट द्वारा काव्य गोष्ठी रचना सक्सेना की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस काव्यगोष्ठी में उमेश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

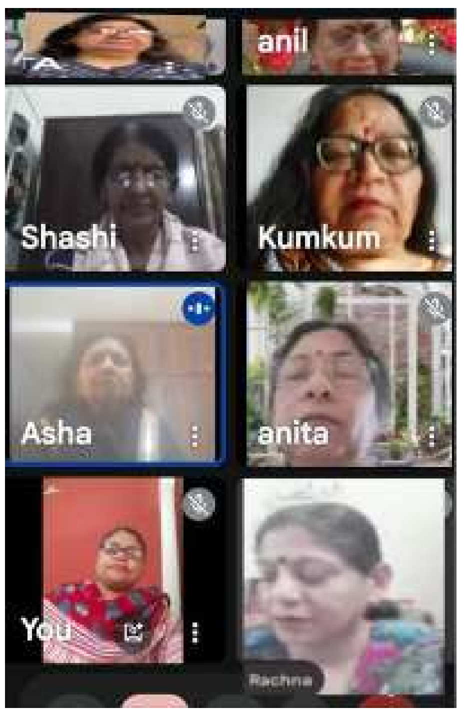

काव्यगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना की सुंदर प्रस्तुति आशा जाकड़ । काव्य गोष्ठी का संयोजन एवं संचालन उमा मिश्रा प्रीति ने किया।

इस काव्य गोष्ठी में अनीता दुबे,सरिता कपूर,रेणुका पटेल, शशि जायसवाल, छाया सक्सेना प्रभु, अर्चना झा अन्नु, डॉ कुमकुम शुक्ला, साधना खरे सुनीता मिश्रा डॉ शोभा त्रिपाठी, डा.अर्चना जैन, मीना परिहार सुनीति केसरवानी रंजना बिनानी। रचनाकार बहनों ने सुंदर रचनाओं की प्रस्तुति द्वारा आयोजन में चार चांद लगा दियें। धन्यवाद ज्ञापन उमा मिश्रा प्रीति ने किया।

50 हजार के इनामी बदमाश अमजद पुलिस मुठभेड़ में ढेर

मुजफ्फरनगर। थाना बुढाना, तितावी और शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अमजद उर्फ अमजद पुत्र जिलेदीन निवासी ग्राम हरसौली, थाना शाहपुर घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल अमजद को तत्काल सीएचसी बुढाना में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में उपनिरीक्षक संदीप कुमार और कांस्टेबल इशफाक भी घायल हुए हैं। दोनों का उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के

मुताबिक अमजद अंतर्राज्यीय स्तर का शातिर अपराधी था, जिसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट सहित संगीन धाराओं में लगभग 40 मुकदमे विभिन्न जनपदों और राज्यों में दर्ज थे।

वह थाना बुढाना में दर्ज मुकदमा संख्या 459/2025 धारा 309(4) बीएनएस तथा मुकदमा संख्या 10/2026 धारा 309(4), 351(3) बीएनएस में वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि वांछित अभियुक्त क्षेत्र में मौजूद है। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में वह घायल हो गया। पूरे प्रकरण की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि मृतक के विरुद्ध मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, दिल्ली, हरिद्वार, बिजनौर, राजस्थान और बिहार सहित कई स्थानों पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट के गंभीर मुकदमे दर्ज थे।

प्रयागराज-हज़रत निज़ामुद्दीन होली विशेष रेलगाड़ी का संचालन

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित होली विशेष रेलगाड़ी (सप्ताह में दो दिन) के संचालन का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

गाड़ी सं. 04123/04124 प्रयागराज-मानिकपुर-हज़रत निज़ामुद्दीन विशेष रेलगाड़ी

गाड़ी संख्या - 04123			गाड़ी संख्या - 04124	
प्रयागराज - हज़रत निज़ामुद्दीन			हज़रत निज़ामुद्दीन - प्रयागराज	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
......	14:50	प्रयागराज	09:10	......
15:25	15:27	शंकरगढ़	07:35	07:37
16:03	16:05	डभौरा	07:05	07:07
16:45	16:50	मानिकपुर	06:30	06:35
17:16	17:18	चित्रकूट धाम कर्वी	04:38	04:40
17:44	17:46	अतर्रा	04:10	04:12
18:35	18:40	बाँदा	03:40	03:45
19:23	19:25	महोबा	02:40	02:42
19:42	19:44	कुलपहाड़	02:00	02:02
20:10	20:12	हरपालपुर	01:35	01:37
21:03	21:05	मऊरानीपुर	01:15	01:17
22:35	22:40	वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी	00:05	00:10
01:05	01:10	ग्वालियर	22:15	22:20
04:20	04:22	धौलपुर	20:23	20:25
06:20	06:25	आगरा कैंट	19:05	19:10
07:50	07:55	मथुरा	18:05	18:10
08:50	08:52	कोसी कलाँ	17:18	17:20
11:35	......	हज़रत निज़ामुद्दीन	......	15:45

• प्रयागराज से गाड़ी संख्या 04123, प्रत्येक बुधवार एवं रविवार, दिनांक : 18.02.2026 से 08.03.2026 • हज़रत निज़ामुद्दीन से गाड़ी संख्या 04124, प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार, दिनांक : 19.02.2026 से 09.03.2026

गाड़ी संरचना : स्लीपर श्रेणी : 08, सामान्य श्रेणी : 09, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी : 01, वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी : 01

नोट: ट्रेन की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाईन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR 323/26(AS)

आरेडिका की उपलब्धियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आरेडिका के महाप्रबंधक पी.के. मिश्रा की हुई सार्थक चर्चा

रायबरेली। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) एवं रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला (पंजाब) के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्रा ने दिनांक 10 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात अत्यंत सौहार्दपूर्ण, प्रेरणादायी एवं सार्थक रही। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री मिश्रा ने आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (आरेडिका) द्वारा अब तक निर्मित 15,000 से अधिक अत्याधुनिक रेल कोचों, आरेडिका में निर्मित फोर्ज्ड व्हीलों, तथा आरेडिका में निर्मित पहली वंदे भारत ट्रेन के निर्माण, उसकी तकनीकी विशेषताओं एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आरेडिका द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों–जैसे जल संरक्षण, हरित ऊर्जा पहल, रेल कौशल विकास योजना तथा व्यापक वृक्षारोपण अभियान पर भी प्रकाश डाला।

महाप्रबंधक श्री मिश्रा ने बताया कि आरेडिका में भू–जल संरक्षण क्षमता बढ़कर 730 मिलियन लीटर हो चुकी है। इन प्रयासों से भारतीय रेलवे की निर्माण क्षमता, तकनीकी दक्षता एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रही उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित होती है। इस दौरान श्री मिश्रा ने भारतीय रेलवे के इतिहास पर आधारित अपनी चर्चित पुस्तक 'रेल्स थ्रू राज' एवं 'टेल्स फ्रॉम रेल्स" की एक–एक प्रति माननीय मुख्यमंत्री को भेंट की। उन्होंने

पुस्तक के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 'रेल्स थ्रू राज' पुस्तक प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है तथा ब्रिटिश काल में भारतीय रेलवे के विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक सामान्य पाठकों के साथ–साथ इतिहास एवं रेलवे विषय शोधकर्ताओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है।

अपनी दूसरी पुस्तक "टेल्स फ्रॉम रेल्स" के बारे में बताया कि भारतीय रेल की आत्मा में उतरने वाली एक अद्वितीय साहित्यिक यात्रा है, जहाँ इस्पात पटरियाँ और भाप के इंजन केवल भौगोलिक दूरियाँ ही नहीं पार करते, बल्कि समय, समाज और साम्राज्य के नियमों को भी पुनर्लेखित किया। मात्र तकनीकी विकास से आगे बढ़ते हुए, बत्तीस कहानियों और निबंधों का यह संग्रह "भूतिया श्रमिकों", आधी रात की डाक गाड़ियों और पटरियों के नीचे दबे बुद्ध की रहस्यमय खोज जैसे विलुप्त संसार को पुनर्जीवित करता है। फ्रांसीसी एन्क्लेवों की उच्चस्तरीय कूटनीति से लेकर जमालपुर की घुड़दौड़ की सामाजिक परंपराओं तक, ये कथाएँ गहन अभिलेखीय शोध को काव्यात्मक और भावपूर्ण गद्य के साथ सहज रूप से पिरोती हैं। यह कृति उस मौन क्रांति का अनिवार्य इतिहास है जिसने आधुनिक भारत की आत्मा को गढ़ा। पुस्तक में रेल से संबंधित कुल 32 सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ संकलित हैं।

चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेल कौशल विकास योजना, भूमि सुधार हेतु कम्पोस्ट खाद एवं जल संरक्षण के लिए आरेडिका द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की तथा कोच निर्माण में गुणवत्ता हेतु विश्वस्तरी मानकों को अपनाने की सलाह दी।

इस अवसर पर पी के मिश्रा के साथ, प्रधान मुख्य इंजीनीयर एस.पी. यादव, सचिव महाप्रबंधक आर एन तिवारी भी मौजूद रहे।

बौद्धिक विचार मंच की ओर से सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन

प्रायागराज। बौद्धिक विचार मंच ऊंचाहार रायबरेली एवं जांबाज हिन्दुस्तानी सेवा समिति प्रतापगढ़ के संयुक्त तत्त्वावधान में बुधवार को संगम अपर मार्ग सेक्टर दो स्थित रुद्र मंडपम शिविर निकट मेला कार्यालय में वेदान्त मर्मज्ञ पूज्य करपात्री जी महराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय तथा अवधी कवि आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त की स्मृति में राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

रज्जू भय्या विश्वविद्यालय के इतिहासकार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. प्रशान्त सिंह शाण्डिल्य मुख्य अतिथि रहे जबकि संस्था महासचिव संस्कृत प्रवक्ता डॉ. पीयूष मिश्र पीयूष ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सर्वप्रथम आयोजक आलोक मिश्र आजाद ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉ. प्रशान्त सिंह शाण्डिल्य ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं मानवीय एकात्मवाद बौद्धिक विचारकों का प्रतिपाद्य प्रयोजन है। राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कवयित्री श्रीमती रिंकी मिश्रा ने पढ़ा जबसे तुम्हें है पाया जीवन नवल हुआ है, तन भी खिला खिला है मन भी धवल हुआ है।

कवि पुष्कर प्रधान ने हृदय हृदय में हिन्दू राष्ट्र पंक्तियां सुनाकर जोश भरा। बालकवि परिमल मिश्र ने भगत बोस शेखर प्रसाद की अमर जवानी है, नमन करो इस मिट्टी के जितनें बलिदानी हैं, हम हिन्दुस्तानी हैं, काव्य पंक्तियां सुनाकर वाहवाही लूटी। कवि अमरेश कुमार सुहृद ने सुनाया सब्र का बांध अब तोड़ देना चाहिए। युवाकवि अमित शर्मा आनन्द ने पढ़ा हमारे देश की खुशियां और बलिदान जिन्दा है। कवि मनीष पाण्डेय, तनु मनु मिश्रा ने ओजपूर्ण काव्यपाठ कर सभी को आह्लादित किया। अध्यक्षीय काव्यपाठ करते हुए डॉ. पीयूष मिश्र पीयूष ने तुम जन मन के भूगोल बने जीवित इतिहास तुम्हीं तो हो, सतरंगी वैभव के नक्षत्र उज्जवल आकाश तुम्हीं तो हो, काव्य पंक्तियां सुनाकर कर मंच को ऊंचाई प्रदान की। लगभग पन्द्रह साहित्यकारों, विद्वानों, समाजसेवियों को बौद्धिक मंच द्वारा सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर महन्त गोकरणदास, डॉ. प्रशान्त सिंह, डॉ. अभिषेक केसरवानी, आलोक मिश्र आजाद, अनिल शर्मा, राकेश सिंह, श्रीमती नीलम मिश्र, पुनीत मिश्र, उत्पल मिश्र, आलोक पाण्डेय, सौरभ पाण्डेय, अंजनी यादव आदि बुद्धिजीवी गण उपस्थित रहे। समाजसेवी राकेश सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

विधि विभाग के 23 विद्यार्थियों ने जेआरएफ, नेट, पीएचडी एडमिशन की परीक्षा में सफलता पाई

प्रयागराज। सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, प्रयागराज के विधि विभाग के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि विभाग के 23 विद्यार्थियों ने जेआरएफ/नेट/ पीएच डी एडमिशन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि से विधि विभाग के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में हर्ष का वातावरण व्याप्त है। सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों में आँचल जायसवाल, अर्चना, अवनीश कुमार, आदित्य चक्रवर्ती, प्रज्ञा दूबे, अजीत वर्मा, वात्सल्य शुक्ला, आशुतोष द्विवेदी, रंजन कुमार प्रसाद, मेघा रानी, देव भारद्वाज, आयुष उपाध्याय, विजय चन्द गौतम, स्वाती यादव, अपूर्वा सिंह, सत्यव्रत तिवारी, खुशी सिंह,

ज्योति मौर्या, ऐश्वर्या सिंह, अथर्व दीक्षित, संजीव कुमार श्रीवास्तव, विवेक झा एवं दीप्ति यादव शामिल हैं। इस अवसर पर विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिव शंकर सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अजय प्रकाश खरे, तथा सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज एलुमनी वेलफेयर एसोसिएशन, प्रयागराज के कार्यकारी सदस्य डॉ. रमेश कुमार भारती ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और अकादमिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रगति का प्रतीक है, बल्कि विधि विभाग की शैक्षणिक गुणवत्ता और मार्गदर्शन परंपरा को भी प्रमाणित करती है।

सभी सफल विद्यार्थियों के उज्ज्वल शैक्षणिक एवं शोधपूर्ण भविष्य की कामना की गई है।

ग्राहकों ने बंद कराई बीओबी की ब्रांच,शटर गिराकर बाहर बैठे

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी में शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच का शटर ग्राहकों ने गिरा दिया। गुरुवार सुबह 25 से अधिक खाताधारक बैंक पहुंचे और अपनी जमा राशि वापस न मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने लगे।

पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वे शटर बाहर से बंद कर वहीं पर बैठ गए। 3 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक का काम बंद है। ज्यादातर ग्राहक बाहर बैठकर नारेबाजी की। दरअसल, इस ब्रांच में शिवा राव नाम के बैंक मित्र ने लोगों की एफडी कराकर उसे खाते में चढ़ाया ही नहीं था। जब एफडी मैच्योर की डेट आई तो लोग बैंक पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि उनकी कोई एफडी हुई ही नहीं थी। कई ग्राहकों के खाते से भी रकम गायब थी। सालिकराम पाल ने बताया कि उनकी बेटी कमला का तिलक कार्यक्रम कल होना है, लेकिन बैंक में जमा किए गए 17 लाख 30 हजार रुपए अब तक वापस नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि परिवार बेहद परेशान है और शादी की तैयारियां अधर में लटक गई हैं।

वसन्त की भोर

है वसन्त की भोर लगे रंजन सब कुंजन।
कलिका यौवन रंग देख अलि करते गुंजन।
प्रकृति वसन्त प्रसंग सुनाने कोयल आयी।
बौराए हैं आम गुलों में मस्ती छायी।
चंचल मन गुन गुन करे प्रिय समझो इस बात को।
मधुर मिलन संवाद को वासन्तिक शुभ रात दो।।

आए हैं ऋतुराज प्रफुल्लित उपवन सारे।
धरा करे श्रृंगार, फूल लगते हैं न्यारे।
हुई मलजयी भोर शाम मदमाती लगती।
रंगों में रँग प्रीत सुहाने पल को रँगती।
दृश्य मनोहर हो गए चंचल दृग चंचला हुई।
यादें सभी अतीत की नवल नवल नवला हुई।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

सीएमपी महाविद्यालय में शिक्षक मंच का कार्यक्रम आयोजित

प्रयागराज। आज सी एम पी महाविद्यालय में शशिक्षक मंचश के तहत श्स्वराराधनश कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिनमें से ए डी सी से प्रो. अर्चना सिंह, ई सी सी से डॉ. पद्मभूषण प्रताप सिंह तथा गजराज सिंह पटेल, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज से डॉ. नम्रता देव, राजर्षि टंडन डिग्री कॉलेज से प्रो. नमिता यादव, के पी बी एड कॉलेज से डॉ. तन्वी वर्मा, ईश्वर

शरण महाविद्यालय से प्रो. अनुजा सलूजा तथा डॉ अमरजीत राम एवं सी एम पी महाविद्यालय से प्रो. अर्चना श्रीवास्तव, प्रो. आभा त्रिपाठी, प्रो. सरिता श्रीवास्तव, केमिस्ट्री विभाग के सभी प्राध्यापक, डॉ. दीपक गौड़, डॉ. दीप्ति विष्णु, डॉ. सत्य प्रकाश श्रीवास्तव आदि ने अपनी मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्राचार्य प्रो. अजय प्रकाश खरे ने सभी अतिथियों का वाचिक स्वागत किया तथा संयोजक प्रो. सुरेन्द्र पाल सिंह ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। समिति के सदस्य डॉ. पवन कुमार यादव तथा डॉ मोनिका सिंह ने पुष्पगुच्छ के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। सभा का संचालन डॉ. दीप्ति विष्णु ने किया। कार्यक्रम में अन्य महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रो. सरोज सिंह, प्रो. भावना चौहान, प्रो. संजय सिंह सहित सी एम पी महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों के साथ सैकडों लोग उपस्थित रहे।

चुनावी बजट से भी वित्तविहीन शिक्षक एवं प्रबंधक हुऐ निराशः डा. कुलदीप मलिक

मुजफ्फरनगर। शिक्षक नेता एवं शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर कुलदीप मलिक के अनुसार यूपी की योगी सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए दसवें बजट से प्रदेश की वित्तविहीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले लगभग तीन लाख शिक्षकों को बड़ी निराशा हाथ लगी है।

डॉक्टर मलिक के अनुसार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये के बजट पेश करते हुए वित्तविहीन शिक्षकों को केवल एक रुपया देकर शिक्षकों के साथ एक घिनौना मजाक करने का कार्य किया है जिससे वित्तविहीन शिक्षकों में शोक की लहर है। उन्होंने बताया हालांकि कल का बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है लेकिन वित्तविहीन

शिक्षकों के लिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। डॉक्टर मलिक ने बताया कि 18वीं विधानसभा में पेश किया गया यह बजट योगी सरकार का दसवां एवं इस कार्यकाल का आखिरी बजट था और इसे चुनावी बजट के रूप में भी देखा जा रहा था जिससे वित्तविहीन शिक्षकों को इस बजट से काफी आशाएं थी लेकिन सरकार ने शिक्षकों की सभी आशाओं पर पानी फेरने का कार्य किया है। डॉक्टर मलिक ने वित्तविहीन शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि भले ही सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों के साथ सरकान ने एक बार फिर धोखा किया हो लेकिन वह वित्तविन शिक्षकों एवं प्रबंधकों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

उत्तर मध्य रेलवे

ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से वरि0 मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियन्ता/समप0/उत्तर मध्य रेल प्रयागराज द्वारा ई-टेन्डर के द्वारा पर्याप्त वित्तीय क्षमता एवं अनुभव सहित प्रतिष्ठित ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिये खुली निविदा, ई-निविदा में वर्णित खुलने के दिनांक को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।

ई-टेन्डर नं0: पीआरवाईजे-सिग-043-2025-26

क्र.सं.:1	निविदा नं.:043	अनुमानित मूल्य (₹ में) : ₹ 190397913.52

कार्य का विवरण :प्रयागराज मंडल छिवकी, नैनी एवं सूबेदारगंज स्टेशनों पर मौजूदा डीसीटीसी के समानांतर एमएसडीएसी की व्यवस्था करके ट्रैक सर्किट की विश्वसनीयता में सुधार का कार्य।

धरोहर राशि (₹ में) : ₹ 1102000/-	निविदा प्रपत्र का मूल्य: 0.00
कार्य समापन की अवधि: बारह माह	निविदा खुलने की तिथि : 09.03.2026

2. निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता : निविदा प्रपत्र www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

3. धरोहर की राशि जमा करना एवं उसका रूप: निविदाओं को उपरोक्त बिड सिक्यूरिटी निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन भुगतान गेटवे द्वारा की जायेगी। यदि निविदा दाता बिड सिक्यूरिटी उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में जीसीसी के अनुसार जमा करते हैं तो उनका निविदा स्वीकार किया जायेगा। यदि निविदादाता द्वारा जमा की गयी बिड सिक्यूरिटी बैंक गारंटी के रूप में है तो यह उचित स्टांप शुल्क के अनुसार होना चाहिये। बैंक गारंटी जमा करते समय यह उ0प्र0 स्टांप अधिनियम 2008 की धारा 13 एवं 24 और समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होना चाहिये। बिना बिड सिक्यूरिटी वाली निविदायें खारिज कर दी जायेंगी।

4. निविदा खुलने का समय तथा स्थान : निविदा पूर्व निर्धारित तिथि 12.30 बजे या उसके बाद ई-निविदा द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक, प्रयागराज के कार्यालय में खोली जाएगी। अगर उस दिन किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहे तो निविदा अगले दिन, कार्य दिवस पर खोली जायेगी।

5. निविदा की वैधता : निविदा खुलने के 90 दिन तक।

6. निविदा डीलिंग हेतु रेलवे के अधिकार : रेलवे प्रशासन का किसी भी समय बिना कारण बताये कोई एक या सारी निविदाओं को स्थगित / संशोधित/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

316/26(DG)

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

सम्पादकीय........

साइबर डकैती पर सख्ती

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख वक्त की जरूरत है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 54 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल फ्रॉड सीधे–सीधे डकैती है। साइबर ठगी खासकर डिजिटल अरेस्ट के जरिये उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाबदेह हितधारकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सीबीआई, बैंकों, आरबीआई की कोताही पर प्रश्न खड़े किए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने लोगों के खून–पसीने की कमाई को बचाने के लिये समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाये हैं। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कतिपय बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना था कि यह कैसे संभव है कि बैंक अधिकारियों की नाक के नीचे साइबर ठग खाताधारकों का करोड़ों रुपया ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कोर्ट ने आशंका जतायी कि इन साइबर ठगी में बैंक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। साइबर ठगी को सीधी डकैती की संज्ञा देते हुए अदालत ने कहा कि इस ठगी पर रोक के लिये केंद्र सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी एसओपी तैयार करे। इतना ही नहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य हितधारकों के लिये चार सप्ताह में एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। बैंकों की कारगुजारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंकों को अहसास होना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं। उन्हें जनता के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि आखिर कैसे साइबर ठगी के लाखों केस सामने आ रहे हैं। अकसर सवाल उठाये जाते रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट व अन्य धोखाधड़ी के मामलों में करोड़ों रुपये साइबर अपराधी दूसरे खातों में डाल रहे होते हैं तो बैंक समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि बैंकों के पास डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से होल्ड करने का भी अधिकार है। इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के पास ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, जिसके जरिये निगरानी हो सके कि कैसे किसी के खाते से निकाली गई बड़ी धनराशि जल्दी–जल्दी दूसरे खातों में हस्तांतरित हो रही है। निश्चित तौर पर बैंकों के सुरक्षा सिस्टम को तत्काल ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को रिजर्व बैंक के बाबत टिप्पणी करनी पड़ी कि साइबर ठगी के जरिये जिन खातों से पैसा ठिकाने लगाया जाता है, उस पर संबंधित बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह सवाल तार्किक है कि अब तक संबंधित बैंक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि यदि बैंक,पुलिस और अन्य एजेंसियां समय रहते तत्काल कार्रवाई करें तो लोगों के खातों में डकैती से हुए नुकसान को कम किया जा सकता है। वैसे एक साल में बाइस लाख साइबर ठगी की शिकायतें सामने आने के बाद कहना कठिन है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां साइबर ठगी के मामलों में तत्काल अंकुश लगा पाएंगी। वक्त की जरूरत है कि पुलिस व अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करके इतना सक्षम बनाया जाए कि वे इन अपराधों की संख्या पर रोक लगा सकें। यह तभी संभव है जब देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और टेलीकॉम अथॉरिटी मिलकर इस दिशा में तुरत–फुरत काम करें। इसके लिये जरूरी है कि पूरे देश में यथाशीघ्र एसओपी लागू किया जाए। जिसके लिये शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक छोटे राज्य के सालाना बजट से अधिक करीब 54 हजार करोड़ रुपये की धनराशि साइबर डकैती से लूट ली गई है। जिसमें राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों की भूमिका बनी हुई है। आज देश के बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व भोले–भाले लोगों को जिस तरह साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार को राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।

मोदी जी, कृपया कभी तो प्रधानमंत्री की तरह बोलिए

अनिल जैन

राज्यसभा में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, उसमें भी न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा और शालीनता का समावेश था और न ही पद की गरिमा व लोकतांत्रिक परंपरा की कोई झलक थी। स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का समापन करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मुद्दों पर अपनी सरकार का नजरिया पेश करते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के दौरान का उनका एक भी ऐसा भाषण याद नहीं आता जो उन्होंने इस विशाल देश के प्रधानमंत्री की तरह दिया हो। अधूरा सच, सफेद झूठ, आधी–अधूरी जानकारी के आधार पर गलत बयानी, तथ्यों की मनमाने ढंग से तोड़–मरोड़, परनिंदा, पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति हिकारत का भाव, नए–नए शिगूफे, स्तरहीन मुहावरे, राजनीतिक विरोधियों पर छिछले कटाक्ष, नफरत भरी सांप्रदायिक तल्खी, धार्मिक व सांप्रदायिक प्रतीकों का इस्तेमाल और भरपूर आत्म प्रशंसा! यही सब प्रमुख तत्व होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में। मौका चाहे देश में हो या विदेश में, संसद में हो या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, चुनावी रैली हो या कोई और अवसर– हर जगह उनके भाषण में अहंकारयुक्त हाव–भाव के साथ यही सारे तत्व हावी रहते हैं। पिछले सप्ताह गुरुवार (5 फरवरी) को राज्यसभा में दिया गया भाषण भी इसका अपवाद नहीं रहा। वैसे तो मोदी को संसद के दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देना था, लेकिन लोकसभा में 4 फरवरी को उन्होंने भाषण नहीं दिया। ऐसा उन्होंने श्लोकसभा स्पीकर के कहने परश् किया। स्पीकर ओम बिड़ला ने बेहद हास्यास्पद और शर्मनाक आशंका जताई थी कि प्रधानमंत्री अगर सदन में भाषण देने आएंगे तो कांग्रेस की कुछ महिला सांसद उन पर हमला कर सकती हैं। स्पीकर की इस आशंका से वह प्रधानमंत्री डरकर सदन में नहीं आए, जिसने तीन साल पहले 10 फरवरी, 2023 को संसद में ही अपनी पीठ थपथपाते हुए बेहद फूहड़ अंदाज में कहा था, देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। बहरहाल राज्यसभा में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, उसमें भी न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा और शालीनता का समावेश था और न ही पद की गरिमा व लोकतांत्रिक परंपरा की कोई झलक थी। स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का समापन करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मुद्दों पर अपनी सरकार का नजरिया पेश करते हैं। इसी क्रम में वे बहस के दौरान विपक्ष के आरोपों और आलोचनाओं का भी जवाब देते हैं। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं किया। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने इस गंभीर मौके पर भी एक मोहल्ला स्तर के नेता की तरह चुनावी भाषण दिया।

कुछ साल पहले फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि श्देश को असली आजादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मिली है।श कंगना की इस बात पर खुश होकर मोदी ने उन्हें सांसद बनवा दिया और गुरुवार को राज्यसभा में कंगना द्वारा कही बात की तर्ज पर ही यह जताने की कोशिश की कि देश ने जो कुछ तरक्की की है, वह उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद की ही है। उन्होंने कहा कि उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें किसी के पास देश को लेकर न तो कोई सोच थी, न कोई दृष्टि और न ही इच्छाशक्ति। उन्होंने देश को बर्बाद करके रखा हुआ था। उन्होंने कहा, श्मैं देशवासियों का आभारी हूं कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया।

हमारी काफी शक्ति उनकी (पूर्व प्रधानमंत्रियों की) गलतियों को ठीक करने में लग रही है। उनके समय जो देश की छवि बनी थी, उसे धोने में मेरी ताकत लग रही है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की आलोचना व निंदा करने का तो मोदी पर मानो जुनून सवार रहता है और इस सिलसिले में जो मुंह में आता है वह बोल जाते हैं। ऐसा करने में वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनकी अशोभनीय गलतबयानी से देश–दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ेगी और लोग उनकी पढ़ाई–लिखाई व उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाएंगे। राज्यसभा में दिए अपने भाषण में भी मोदी ऐसा करना नहीं भूले। इस सिलसिले में उन्होंने इंदिरा गांधी के ईरान में दिए गए एक भाषण के हवाले से कहा कि, श्जवाहरलाल नेहरू के समय देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी और नेहरू कहते थे कि मेरे सामने 35 करोड़ समस्याएं हैं।श इसी तरह इंदिरा गांधी के समय देश की जनसंख्या 57 करोड़ थी और इंदिरा जी ने कहा था कि, श्मेरे सामने 57 करोड़ समस्याएं हैं।श मोदी का यह बताना या तो उनकी क्षुद्रता का परिचायक है या फिर उनकी नासमझी का। यह उनके भाषण के नोट्स बनाने वाले नौकरशाहों की शरारत भी हो सकती है कि उन्होंने मोदी को गलत नोट्स बनाकर थमा दिए हों जिन्हें मोदी ने संसद में पढ़ दिए। दरअसल नेहरू से जब किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि श्आपके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो नेहरू ने कहा था कि देश के 35 करोड़ लोगों की समस्याएं मेरी समस्या हैं और इसी तरह इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश के 57 करोड़ लोगों की समस्याओं को मैं अपनी समस्या मानती हूं। प्रधानमंत्री अपने भाषण का स्तर गिराने में यहीं नहीं ठहरे। इसके भी नीचे उतरते हुए उन्होंने कहा कि श्चोरी करना नेहरू–गांधी परिवार का पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती महात्मा गांधी का सरनेम तक चुरा लिया।श वैसे अव्वल तो कोई क्या सरनेम लगाता है, यह बहस का विषय नहीं हो सकता और संसद में तो कतई नहीं, फिर भी अगर मोदी को इसका शौक है तो उन्हें इस बारे में बोलने से पहले यह जान लेना चाहिए कि गांधी सरनेम किसी जाति या संप्रदाय विशेष में नहीं होता है बल्कि यह इत्र–फुलेल से जुड़े व्यवसाय से ताल्लुक रखता है। यह सरनेम सिर्फ वैश्य वर्ग में ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, पारसी आदि समुदायों में भी होता है। मोदी ने यह सिलसिला सिर्फ चुनावी सभाओं तक ही सीमित नहीं रखा है। संसद में, संसद के बाहर विभिन्न मंचों पर और यहां तक कि विदेशों में भी वे विपक्षी नेताओं पर निजी हमले और अपमानजनक बातें करने से नहीं चूकते हैं। फिर, विपक्ष शासित राज्यों के प्रति उनकी सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार ने भी केंद्र और राज्यों के बीच खटास पैदा कर दी है।

दरअसल विरोधी दलों और उनके नेताओं के प्रति मोदी की अपमानजनक बातें शुरू में जरूर अटपटी लगती थीं। चूंकि भाजपा और मोदी ने काफी बड़ी जीत हासिल की थी, इसलिए विपक्षी नेताओं ने उनकी ऐसी बातों को यह सोचकर बर्दाश्त किया कि जीत की खुमारी उतर जाने पर प्रधानमंत्री राजनीतिक विमर्श में सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार और भाषायी शालीनता का पालन करने लगेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ और लगने लगा कि यही मोदी की स्वाभाविक राजनीतिक शैली है और वे बदलने वाले नहीं हैं, तब विपक्षी नेताओं के सब्र का बांध टूटा और उसमें सारी राजनीतिक शालीनता और मर्यादा बहती चली गई। देश में शायद ही कोई ऐसा विपक्षी मुख्यमंत्री या नेता होगा जिसके लिए पीएम ने सार्वजनिक रूप से अपमानजनक बातें या गाली–गलौज नहीं की होगी। मोदी उन्हें भ्रष्ट, परिवारवादी, लुटेरा, नक्सली, आतंकवादियों का समर्थक और देशद्रोही तक करार देने में कोई संकोच नहीं करते। इस सिलसिले में वे विपक्ष की महिला नेताओं को भी नहीं बख्शते। वे उनके लिए बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। विपक्षी नेताओं के प्रति मोदी के अपमानजनक बर्ताव का ही नतीजा है कि आज केन्द्र–राज्य संबंध किसी भी समय के मुकाबले सबसे बदतर स्थिति में हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब मोदी किसी विपक्ष शासित राज्य के दौरे पर गए तब वहां के मुख्यमंत्री उनकी आगवानी करने नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री ने तमाम विपक्षी दलों को अपने, अपनी पार्टी और देश के दुश्मन के तौर पर प्रचारित करते हुए उन्हें खत्म करने का खुला ऐलान किया है। वे हर जगह डबल इंजन की सरकार का ऐसा प्रचार करते हैं, जैसे विपक्ष की सारी सरकारें जनविरोधी, देश–विरोधी और विकास–विरोधी हैं। मोदी की इस राजनीति ने विपक्षी पार्टियों को सोचने पर मजबूर किया है। इसलिए आज अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर आंच आ रही है और उनकी बेअदबी हो रही है तो इसके लिए प्रधानमंत्री का अंदाज–ए–हुकूमत और अंदाज–ए–सियासत ही जिम्मेदार है। कितना अच्छा होता कि मोदी भाषा और संवाद के मामले में थोड़ी सी तहजीब और नफासत पसंद या सुरुचिपूर्ण होते, जितने वे पहनने–ओढ़ने और सजने–संवरने के मामले में हैं। एक देश अपने प्रधानमंत्री से इतनी सामान्य और जायज अपेक्षा तो रख ही सकता है। उनका बाकी अंदाज–ए–हुकूमत चाहे जैसा भी हो।

देश की सुरक्षा और सच-झूठ की परीक्षा

पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब श्फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनीश पर सियासी घमासान अब सच और झूठ की परीक्षा में तब्दील हो चुका है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस किताब की प्रति पिछले हफ्ते ही संसद में लेकर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह किताब देंगे, ताकि वे खुद उन बातों और तथ्यों को पढ़ सकें, जिन्हें लोकसभा में पढ़ने से राहुल गांधी को रोका गया। लेकिन नरेन्द्र मोदी इसके बाद लोकसभा में पहुंचे ही नहीं और न ही राहुल गांधी से उनका सामना हुआ। हालांकि यह एक अच्छा मौका नरेन्द्र मोदी के पास था, जब वे एक साथ अपनी देशभक्ति, बहादुरी और 56 इंची सीने की सच्चाई देश–दुनिया को दिखा देते। राहुल गांधी का कहना है कि नरेन्द्र मोदी एक किताब से डर गए, क्योंकि इसमें चीन के घुसपैठिया अभियान की हकीकत बयां की गई है। श्री मोदी चाहते तो राहुल गांधी से ये किताब लेकर साबित कर देते कि वे डरे हुए नहीं हैं और जो कुछ उस किताब में लिखा है उसे भी पढ़ लेते। अगर कुछ गलत लिखा है तो उसकी सच्चाई बता देते, इससे उनका ही हाथ ऊंचा होता। लेकिन बजाए इतना सीधा सा काम करने के, अब इस मामले को कानूनी पचड़े में उलझा दिया गया है। अब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब की सॉफ्ट कॉपी के ऑनलाइन प्रसारित होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है, श्हमने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिलने पर जांच शुरू की। किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा तैयार की गई लगती है, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से यह अभी अप्रकाशित है। स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच चल रही है। गौरतलब है कि किताब में जनरल नरवणे ने लिखा है कि 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव के दौरान जब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य नेताओं को जानकारी दी कि, चीनी टैंक आ रहे हैं, तो लंबे समय तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला। करीब ढाई घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया–जो उचित समझो, वो करो। राहुल गांधी इसी पर सरकार से जवाब चाह रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, मुझे यकीन है कि यह किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई।श उन्होंने राहुल गांधी से कहा, जो किताब का दावा कर रहे हैं, उसे सदन में पेश करें, हम देखना चाहते हैं।

सरकार द्वारा ऐसी किसी किताब के छपे होने के दावे को खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने 4 फरवरी को संसद परिसर में किताब की प्रकाशित प्रति दिखाई और पत्रकारों से कहा, देखिए, किताब है, सरकार कह रही है कि किताब नहीं है। बता दें कि फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा है। जनरल नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख रहे। किताब में उनकी 40 साल की सेवा, सिक्किम में उनके पहला आमना–सामना, गलवान संघर्ष, पाकिस्तान के साथ सीजफायर आदि का जिक्र है। किताब 448 पेज की है और अप्रैल 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली।

ग़ज़ल

माँ का आँचल बाप की चादर नहीं थे।
शहर जैसे भी थे मेरा घर नहीं थे

जिसके साए में हमारी बैठकें थीं।
उस शजर की शाख़ पे ताइर नहीं थे

दीनो–ईमाँ को हमारे ज़ब्ह करते।
दरिन्दे हाथों में वे ख़ंजर नहीं थे

हम मुहाजिर की तरह तन्हा जहाँ थे।
हमसफ़र उन राहों पे अक्सर नहीं थे

इश्क़ करना, इश्क़ पाना ही न जाना।
चूम लेते सातों अम्बर पर नहीं थे

इन कलमकारों की सोहबत फ़लसफ़ा है।
कह ना देना दौर में रहबर नहीं थे

—डॉ० अवनीश यादव
पी0ई0एस0

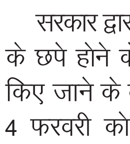

रचना सक्सेना की कुण्डलियाँ

हरियाली की ओट में, ये पुरखों के गाँव।
लहराते थे खेत भी, मिलती ठंडी छाँव।।
मिलती ठंडी छाँव, कूकती कोयल काली।
जीवन भी था शाँत, छटा भी बड़ी निराली।।
कहती रचना आज, खुशी से होता खाली।
जीवन भागमभाग, कहाँ मिलती हरियाली ।।

पीपल जैसी छाँव थी, पुरखों के वो गाँव।
बच्चो मे संस्कार थे, छूते सबके के पाँव।।
बड़ों के छूते पाँव, सरल जीवन था सादा।
मिट्टी के घर द्वार, प्यार भी सबमें ज्यादा।।
कहती रचना आज, हवा कब मिलती शीतल।
दूषित होता गाँव, कटे जब बरगद पीपल।।

रचना सक्सेना
अलोपीबाग
प्रयागराज

मोदी–शाह के दौरों के बावजूद भगवा पार्टी का मनोबल अधिक मजबूत नहीं हुआ

तीर्थंकर मित्रा

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हराने की बात कहना भाजपा के लिए जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, भले ही भाजपा नेता इस साल अप्रैल–मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने की बात कर रहे हों। पूरी कोशिश करने के बावजूद लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद, भगवा पार्टी की 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीदें सत्ता विरोधी भावना, पूरे बंगाल में हिंदू एकजुटता, और टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कहानी पर टिकी हैं। इन मुद्दों के आधार पर, इस चुनावी राज्य में भाजपा का प्रचार टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करिश्मे और उनकी सरकार के उन लोकप्रिय परियोजनाओं के खिलाफ होगा, जिनसे उन्हें चुनावी फायदा हुआ था। टीएमसी के इन चुनावी प्लेटफॉर्म से पार पाना भगवा खेमे के लिए अब तक की सबसे मुश्किल चुनावी परीक्षा होगी। टीएमसी नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना भाजपा के लिए सबसे अच्छा दांव लगता है क्योंकि वह चुनाव प्रचार शुरू करने वाले है। रुपये के बदले नौकरी देने का आरोप और टीएमसी के पूर्व महासचिव और शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के सहयोगी के घर से मिले नकदी के बंडल और आरजीकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर के बलात्कार और उसकी हत्या ने टीएमसी नेतृत्व को मुश्किल में डाल दिया है। इसके साथ ही, भगवा खेमे की नजर सत्ताविरोधी कारक और हिंदू वोटों के एकजुट होने पर है। सत्ताविरोधी कारक इसलिए बेअसर है क्योंकि राज्य के भगवा खेमे के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जा सके। भगवा खेमा का हिंदू वोटों का समीकरण सही नहीं है। हो सकता है कि समुदाय सत्ताधारी सरकार से खुश न हो, लेकिन इसके भाजपा को एक साथ वोट देने की उम्मीद कम है। हालांकि विपक्ष के नेता, शुभेंदु अधिकारी अब तक के सबसे लोकप्रिय और दिखने वाले भाजपा नेता हैं, लेकिन उनके अपने खेमे में भी उनके विरोधी हैं। राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया है कि वे तब से भाजपा में हैं जब शुभेंदु तृणमूल में थे और ममता बनर्जी के खास सिपहसालार थे। इसके अलावा, टीएमसी संगठन के मामले में भाजपा से बहुत आगे है। तृणमूल के सांगठनिक नेटवर्क ने पार्टी को संभाला, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी राज्य में आए हों और चुनावी माहौल को और गरमाया हो। हालात ऐसे हो गए हैं कि भगवा खेमा अपनी सांगठनिक कमजोरी को ठीक करने के लिए राज्य से किसी नेता को नहीं ला सका। इसने पिछले सितंबर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी चुना और उन्हें पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने का काम सौंपा। केंद्रीय नेतृत्व के इस आदमी ने जमीनी नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन राज्य के भगवा खेमे के सूत्रों ने बताया कि यादव को उन्हें दिए गए काम के लिए समय काफी नहीं लगा। सूत्रों ने बताया कि राज्य भाजपा के पास बूथ लेवल के इतने कार्यकर्ता नहीं हैं जिनकी मौजूदगी या गैरमौजूदगी मतदान के दिन किसी उम्मीदवार की जीत या हार तय कर सके। जबकि ये कार्यकर्ता 2021 के विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन बाहर रहते तो भगवा खेमे में विधायकों की संख्या और ज़्यादा होती। इस बीच, तृणमूल प्रमुख अपनी 2021 की रणनीति को जारी रखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को श्बाहरीश कहती रही हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) की पृष्ठभूमि में, पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय कोई भी श्बाहरीश का टैग नहीं लगवाना चाहता। गुमशुदा लोगों ने पहले ही भाजपा के विधायकों की संख्या कम कर दी है। ममता बनर्जी का करिश्मा और टीएमसी की लगातार तीन जीत आने वाले चुनावों में भगवा खेमे के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए बहुत से लोगों को उत्सुक नहीं करेंगी। एसआईआर को लेकर चिंता और मतुआ समुदाय में भाजपा नेतृत्व में फूट आने से आने वाले चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके भाई, भाजपा विधायक सुब्रत ठाकुर के बीच सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ है। मतुआ पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में फैला एक दलित धार्मिक ग्रुप है, जिसके भारी समर्थन की वजह से 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को शानदार नतीजे मिले थे। वे भगवा खेमे और उसके कार्यनिष्पादन की मजबूती रहे हैं, हालांकि इस बात पर शक है कि इसे दोहराया जा सकेगा। भगवा खेमे के लोकप्रिय नेता बहुत ज़्यादा अगर–मगर पर निर्भर लग रहे हैं। राज्य भाजपा के कुछ बड़े नेताओं को लगता है कि कई मुस्लिम ग्रुप टीएमसी की नाकामी से नाखुश हैं, जो उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की लिस्ट से बाहर होने से नहीं रोक पाई, इस बार भाजपा को वोट देंगे। लेकिन इस सोच के चक्कर में, इन नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के कई वर्गों को बाहरी और घुसपैठिए बताने की अपनी ही बात को नजरंदाज कर दिया है। अगर ये अल्पसंख्यक वर्ग के एक विशेष खेमे के लोग अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल भी लेते हैं, तो भगवा खेमा आखिरी पार्टी होगी जिसे वे वोट देंगे। इन अल्पसंख्यकों को वर्तमान में चल रही एसआईआर अभियान के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर होने का डर है। भाजपा के साथ अपने पिछले अनुभव को देखते हुए, उन्हें लगता है कि भगवा पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन्हें कम अहमियत मिलेगी। एसआईआर अभ्यास के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान करने के आरोप लगाने के बाद टीएमसी प्रमुख पर नाटक करने का आरोप लगा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की जनता के हित में उनकी बहस ने उनके मतदाताओं के लिए एक संदेश दिया है, जो शायद उनके मतदान करने के तरीके में दिखेगा।

इश्क बदला तो सुजैन ने निभाई दोस्ती, प्रकाश कौर ने दुनिया को दिया मुंहतोड़ जवाब

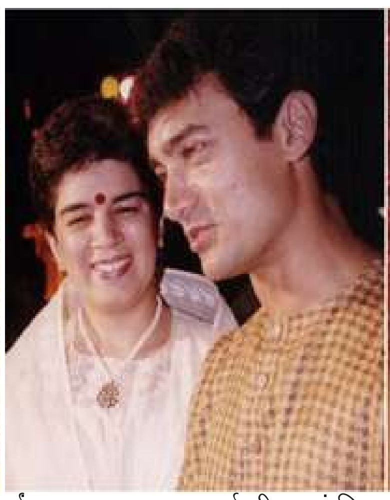

दीप्ति मिश्र के लिखे ये शब्द बॉलीवुड के कई कपल के रिश्ते पर सटीक बैठते हैं। बॉलीवुड की कुछ जोड़ियां ऐसी ही हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ प्यार से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता निभाया। जब रिश्तों में किसी तीसरे की एंट्री हुई तो उन्होनें न सिर्फ उन्हें अपनाया बल्कि समाज में इज्जत भी दिलाई। सलमान खान की इश्क की कई दास्तां हैं। मगर उनके पिता सलीम भी इश्क में हाथ आजमाने से कभी पीछे नहीं रहे। सलीम की पहली मोहब्त थीं सुशीला चरक। मुंबई के माहिम इलाके में दोनो एक–दूसरे के पड़ोसी थे। 17 साल की सुशीला से 24 साल के सलीम रोज मिलने लगे और दोनों को एक–दूसरे से प्यार हो गया। सुशीला के पिता डेंटिस्ट थे और सुशीला की शादी करवाना चाहते थे। उन्हें सलीम पसंद आए और रिश्ता तय हुआ। शादी के बाद सुशीला को नया नाम मिला– सलमा खान। आगे चलकर सलीम मशहूर फिल्म राइटर बने। 1978 में फिल्म 'डॉन' के सेट पर पहली बार उनकी मुलाकात हेलेन से हुई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और सलीम काम दिलाने में उनकी मदद करने लगे। कुछ वक्त बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और चार साल बाद 1980 में सलीम ने हैलेन ने शादी कर ली। इस बात ने सलमा खान को गहरा झटका तो दिया मगर आगे चलकर उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हेलेन ने भी सलमा के बेटों सलमान, सोहेल और अरबाज को मां की तरह अपनाया। आगे चलकर सलीम और हेलेन ने अर्पिता खान को गोद लिया। आज खान परिवार के हर छोटे–बड़े फैमिली इवेंट में सलीम, सलमा और हेलेन एक साथ नजर आते हैं। सलमा खान का सलीम के प्रति सच्चा प्यार और उनका समर्पण आज भी उनके परिवार को जोड़कर रखता है।

बॉलीवुड के ही–मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी। इस अरेंज मैरिज के वक्त धर्मेंद्र मात्र 19 साल के थे और प्रकाश 17 कीं। आगे चलकर 50 के दशक में धर्मेंद्र एक्टर बनने मुंबई आ गए। वहीं प्रकाश ने घर पर रहकर बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाया। रिश्ते को धक्का तब लगा जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच इश्क की चर्चा शुरू हुई। प्रकाश को भी इसका अंदाजा हो गया लेकिन चार बच्चों की मां ने धैर्य से काम लिया।

धर्मेंद्र की भावनाओं को एक दोस्त की तरह समझा और हेमा से शादी की इजाजत दे दी। हालांकि, यह शर्त रखी कि धर्मेंद्र कभी भी प्रकाश को तलाक नहीं देंगे। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने शादी कर ली। इस शादी के बाद जब दोनों की आलोचना हुई तो प्रकाश ने ही दोनों का सपोर्ट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो लोगों को क्या ही तकलीफ है? हेमा ने अपनी आत्मकथा में बताया था कि वो धर्मेंद्र से शादी करने से पहले एक–दो बार उनकी पत्नी से मिली थीं पर शादी के बाद वो कभी उनके सामने नहीं गईं। प्रकाश ने सबकुछ सहा पर कभी अपना घर टूटने नहीं दिया।

प्रोड्यूसर बोनी कपूर की पहली शादी मोना सिंह से साल 1983 में हुई थी। तब मोना 19 और बोनी 29 साल के थे। 1987 तक तो दोनों के जीवन में सबकुछ ठीक चला पर फिर 'मिस्टर इंडिया' के सेट पर बोनी की मुलाकात श्रीदेवी से हुई। कुछ साल बाद जब श्रीदेवी का मिथुन से तलाक हो गया तो उन्हें संभालते–संभालते बोनी खुद अपना दिल खो बैठे। कुछ साल तक तो यह रिश्ता मोना से छिपा रहा पर आगे चलकर जब उन्हें इस बात की भनक लगी ते उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक इंटरव्यू में मोना ने कहा था– 'बोनी मुझसे 10 साल बड़े थे तो मैं तो लगभग उनके साथ ही बड़ी हुई हूं। 13 साल की शादी के बात जब मुझे पता चला कि मेरे पति किसी और से प्यार करते हैं तो यह मेरे लिए सदमे की तरह था। मैं इस रिश्ते में कुछ कर भी नहीं सकती थी।'

1996 में मोना ने चुपचाप बोनी को तलाक दे दिया। उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बच्चों अर्जुन और अंशुला को पाला। वहीं, बोनी को श्रीदेवी से दो बेटियां जान्हवी और खुशी हुईं। साल 2012 में कैंसर जैसी बीमारी के चलते मोना का निधन हो गया। आज बोनी अपने चारों बच्चों के साथ रहते हैं और आपस में उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है। आमिर और रीना कभी पड़ोसी हुआ करते थे और खिड़कियों से एक–दूसरे को देखा करते थे। दोनों में प्यार बढ़ा और अपने 21वें जन्मदिन के तुरंत बाद आमिर ने अप्रैल 1986 में रीना से कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी के बारे में दोनों ने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया।

हालांकि, डेब्यू फिल्म की रिलीज से पहले ही दोनों परिवारों को आमिर और रीना की शादी के बारे में पता चला। इसके बाद अपनी चॉकलेट बॉय और सिंगल इमेज को बनाए रखने और फिल्म के बिजनेस पर बुरा असर पड़ने से बचाने के लिए कपल ने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया। 1988 में रिलीज हुई आमिर की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक के लोकप्रिय गाने पापा कहते हैं में रीना दत्ता एक छोटी सी भूमिका में नजर आई थीं। हालांकि, उस समय तक किसी को पता नहीं था कि वे आमिर की पत्नी हैं।

वक्त बीता और कपल के दो बच्चे हुए। बेटा जुनैद और बेटी आयरा। इस दौरान जब आमिर ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो पहली फिल्म 'लगान' के काम की जिम्मेदारी भी रीना ने संभाली। और फिर इसी फिल्म के सेट पर रीना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शादी के 16 साल बाद, साल 2002 में आमिर और रीना ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। आमिर ने हाल ही में स्वीकार किया कि इतनी कम उम्र (21) में शादी करना उनकी भूल थी और काम के प्रति उनके जुनून ने भी इस रिश्ते पर असर डाला।

रीना के जीवन से जाने के बाद आमिर ने किरण राव से शादी की। किरण और आमिर की मुलाकात फिलम श्लगानश के सेट पर हुई थी, जहां किरण एक असिस्टेंट डायरेक्टर थीं। उस समय दोनों के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। आमिर अपनी पहली पत्नी रीना के साथ शादीशुदा थे और किरण किसी और को डेट कर रही थीं। हालांकि, 2002 में रीना से तलाक लेने के बाद जब आमिर कठिन दौर से गुजरे तब उनकी और किरण की बातचीत दोबारा शुरू हुई। एक रात किरण से 30 मिनट फोन कॉल पर बात करने के बाद उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई, जिसके बाद वो अक्सर देर रात बात करने लगे और 2004 में उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। 28 दिसंबर 2005 को पंचगनी में एक निजी समारोह में दोनों की शादी हुई और 2011 में सरोगेसी के जरिए किरण के बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ।

किरण से 15 साल की शादी के बाद जुलाई 2021 में आमिर ने उनसे भी तलाक ले लिया। उन्होंने इसे 'रिश्ते का अंत' नहीं, बल्कि 'रिश्ते का बदलाव' बताया था। इन दिनों आमिर, गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। तलाक के बाद आज भी आमिर, रीना और किरण के बीच गहरा सम्मान और दोस्ती का रिश्ता कायम है। तीनों अक्सर पब्लिक इवेंट और पारिवारिक कार्यक्रमों में साथ नजर आते हैं।

ऋतिक रोशन और सुजैन खान के प्यार से ज्यादा लोग इनकी दोस्ती की चर्चा करते हैं। दोनों की कहानी एक ट्रैफिक सिग्नल से शुरू हुई थी। दोनों की कारें अगल–बगल आईं, ऋतिक ने सुजैन को देखा और वो उनके लिए पहली नजर का प्यार बन गईं। एक्टर ने अपने दोस्त संजय कपूर को इस बारे में बताया और उनकी मदद से ही सुजैन का पता लगाया। साल 2000 में दोनों ने शादी कर ली। 13 साल तक सबकुछ ठीक रहा पर दिसंबर 2013 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया और नंवबर 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया। अब दो अपने बच्चों (दो बेटे) की पैरेंटिंग साथ करते हैं। जहां ऋतिक इन दिनों सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में हैं वहीं सुजैन, अर्सलान गोनी को डेट कर रही हैं।

म्यूजिकल ड्रामा बैंडवाले का दिल को छू लेने वाला ट्रेलर रिलीज

भारत में दर्शकों के मनोरंजन के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपनी आगामी म्यूजिकल ड्रामेडी सीरीज "बैंडवाले" का दिल छू लेने वाला ट्रेलर लॉन्च किया। यह प्राइम ओरिजिनल सीरीज अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे द्वारा लिखी और तैयार की गई है, जबकि निर्देशन अक्षत वर्मा और अंकुर तिवारी ने किया है। सीरीज का निर्माण ओएमएल एंटरटेनमेंट कर रहा है। कहानी में संगीत एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसमें यशराज मुखाटे की ओरिजिनल रचनाएँ शामिल हैं, जो उनके पहले लॉन्ग फॉर्मेट सीरीज की रचना होगी. कौसर मुनिर की खूबसूरत कविताएँ कहानी की भावनात्मक गहराई को और निखारती हैं। बैंडवाले में मुख्य भूमिकाओं में शालिनी पांडे, जहान कपूर, स्वानंद किरकिरे, संजना दीपू, आशिष विद्यार्थी, और अनुपमा कुमार शामिल हैं। सीरीज का प्रीमियर 13 फरवरी को प्राइम वीडियो पर होगा, और यह भारत के साथ–साथ दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से उपलब्ध होगी। ट्रेलर एक ऐसी कहानी का स्वर स्थापित करता है जो रचनात्मकता, दोस्ती और शांत बगावत पर आधारित है, और छोटे शहर के सपने देखने वालों की भावनात्मक धड़कन को पकड़ता है, जो अपनी आवाज ढूंढ रहे हैं। रतलाम के बीचों–बीच सिथ्त, बैंडवाले में मरियम नाम की एक युवा कवियत्री की कहानी है, जो अपनी पहचान, आजादी और अपनेपन के सवालों से जूझते हुए बिना नाम बताए अपनी रचनाएँ ऑनलाइन शेयर करना शुरू करती है। उसकी यात्रा रोबो और डीजे सायको के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ तीनों संगीत, हास्य और साझा महत्वाकांक्षा पर भरोसा करते हुए अपने हालात से परे जीवन की कल्पना करते है। ट्रेलर उनके आपसी रिश्ते, रचनात्मक बेचौनी और उस नाजुक आशा की झलक दिखाता है कि कला न केवल निकलने का रास्ता बन सकती है, बल्कि आगे बढ़ने का मार्ग भी। संगीत कहानी के भावनात्मक पहलू को आगे बढ़ाता है और स्वयं कथा का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। डीजे सायको कुछ हद तक रहस्यपूर्ण किरदार है, रतलाम में हर तरह के अजीबो–गरीब काम करता है, वह गहराई से महसूस करता है लेकिन अपनी भावनाओं को बीट्स और साउंड के जरिए सहयोगात्मक संगीत में व्यक्त करता है," जहान कपूर ने कहा। "वह हमेशा लो प्रोफाइल में रहकर काम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जब तक वह मरियम से नहीं मिलता, और बेशक रोबो से भी। वह उनके जीवन में पूरी तरह शामिल हो जाता है, और उसका पिछला जीवन कोने में किसी छाया की तरह मंडराता रहता है। उसे निभाना मेरे लिए बेहद मुक्तिदायक अनुभव था क्योंकि इसने मुझे संगीत और साउंड डिजाइन से जुड़े नए भावनाओं और रिश्तों का पता लगाने की अनुमति दी। अंकुर तिवारी, स्वानंद किरकिरे, अक्षत वर्मा और प्राइम वीडियो व ओएमएल द्वारा तैयार की गई पूरी टीम के साथ काम करना वास्तव में एक समृद्ध अनुभव रहा। 'बैंडवाले' की शूटिंग के दौरान मैंने खुद को एक शानदार टीम से घिरा पाया, जो सच्ची और बहु–स्तरीय कहानी कहने में मदद कर रही थी, और मुझे मुझ पर रखे गए अपार भरोसे के लिए आभार है। 'बैंडवाले' मेरे साथ लंबे समय तक बना रहा। मैं बेहद उत्साहित हूँ कि हमारी यह 'कमिंग–ऑफ–एज' म्यूजिकल साहसिक यात्रा हर घर में प्राइम वीडियो पर उपलब्ध होगी।""मरियम वह व्यक्ति है जो लगातार अपने भीतर की भावनाओं और दुनिया की उससे अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है," शालिनी पांडे ने कहा। "कविता उसके लिए सबसे ईमानदार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, एक ऐसा स्थान जहाँ वह बिना डर या अनुमति के अपने आप को सहज रूप में व्यक्त कर सकती है। उसे निभाना मेरे लिए एक बेहद व्यक्तिगत यात्रा रही, जिसमें मैंने मौन, संयम और अपनी आवाज को धीरे–धीरे खोजने के साहस को समझा। प्राइम वीडियो के साथ, 'बैंडवाले' ने मुझे उन भावनात्मक बदलावों का अनुभव करने का मौका दिया, जो अक्सर छोटे शहरों के जीवन को आकार देते हैं।

बिना इजाजत गर्भाशय निकालवा दिया..उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना के गंभीर आरोप, सिंगर के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर

बॉलीवुड के जाने–माने प्लेबैक सिंगर उदित नारायण एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। मामला उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा है। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सिंगर पर संगीन आरोप लगाते हुए सुपौल के महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में रंजना ने आरोप लगाया है कि उदित नारायण ने उनके साथ ध ाोखे किया। उन्होंने दावा किया कि सिंगर ने इलाज के बहाने उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ले जाकर बिना उनकी अनुमति के उनका गर्भाशय निकालवा दिया। रंजना के अनुसार उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और यह उनके साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। रंजना ने इसके अलावा उत्पीड़न और वादाखिलाफी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि इस घटना के कारण उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ और वह लंबे समय से बीमारी और तंगहाली का सामना कर रही हैं। बता दें, रंजना और उदित नारायण की शादी 7 दिसंबर 1984 को हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उदित नारायण अपने करियर के चलते मुंबई चले गए, जिससे उनके और रंजना के बीच दूरी बढ़ने लगी। बाद में रंजना को मीडिया से पता चला कि उदित नारायण ने दूसरी शादी कर ली है। जब उन्होंने सिंगर से इस बारे में सवाल किया, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रंजना के मुताबिक, 1996 में उन्हें सबसे बड़ा धोखा मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें इलाज के नाम पर दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनके बिना अनुमति के गर्भाशय को निकाल दिया गया। रंजना ने इसे एक वेल प्लान्ड साजिश करार दिया और कहा कि इस घटना ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह प्रभावित किया। रंजना नारायण झा की यह शिकायत सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से चर्चा का विषय बन गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और अदालत इस मामले में क्या कार्रवाई करती हैं।

प्राइम वीडियो ने अनिल कपूर की आने वाली दमदार हिंदी एक्शन–ड्रामा फिल्म सूबेदार के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा की

भारत में दर्शकों के मनोरंजन के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपनी आने वाली प्राइम ऑरिजिनल एक्शन–ड्रामा मूवी सूबेदार के वर्ल्डवाइड प्रीमियर की घोषणा की, जो 5 मार्च को प्रीमियर के लिए तैयार है। तुम्हारी सुलु, जलसा और दलदल के जरिए बेहतरीन कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मशहूर, सुरेश त्रिवेणी ने फिल्म सूबेदार का निर्देशन किया हैं और इसे विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर, और सुरेश त्रिवेणी ने साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। ओपनिंग इमेज फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ मिलकर तैयार की गई ये फिल्म बेहद दमदार और जज्बातों से भरी एक्शन–ड्रामा है। सूबेदार की कहानी सुरेश त्रिवेणी और प्रज्वल चंद्रशेखर ने लिखी है जिसमें अनिल कपूर और राधिका मदान मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, साथ ही सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैजल मलिक और मोना सिंह ने भी अहम किरदार निभाए हैं। 5 मार्च को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों एवं क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में सूबेदार का प्रीमियर होगा। सूबेदार फिल्म में एक रिटायर्ड फौजी, सूबेदार अर्जुन मौर्या की जिंदगी के उतार–चढ़ाव भरे सफर को दिखाया गया है, जो आज की बदलती दुनिया में सुकून पाने की तलाश में है, जहाँ उसके उन उसूलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसके सहारे उसने जिंदगी बिताई है। फिल्म में अनिल कपूर ने जबरदस्त अभिनय किया है, जो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, साथ ही अपने बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश करते हुए हमेशा सही का साथ देते हैं। भारत का हृदयस्थल में बसी, इस फिल्म में समाज के गिरते स्तर के बीच सम्मान तलाशने की दमदार कहानी को बड़ी संजीदगी से पर्दे पर दिखाया गया है। प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और ऑरिजिनल्स के हेड, निखिल मधोक ने कहा, सूबेदार एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होने के साथ–साथ बाप–बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी भी है। इस फिल्म में अनिल कपूर का अभिनय शानदार है, जो एक एक्शन हीरो के तौर पर शुरू से ही दर्शकों का दिल जीत लेंगे। सुरेश त्रिवेणी, अनिल कपूर, विक्रम मल्होत्रा और सूबेदार की पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना हमारे लिए गौरव की बात है। अब हमें 5 मार्च का बेसब्री से इंतजार है जब भारत और दुनिया भर के दर्शक प्राइम वीडियो पर इसके प्रीमियर का आनंद लेंगे। ओपनिंग इमेज फिल्म्स के पार्टनर और सूबेदार के प्रोड्यूसर, विक्रम मल्होत्रा ने बताया, "सूबेदार सही मायने में जबरदस्त फिल्म है, और इस तरह के मुख्य किरदार को शायद दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो देश सेवा, अनुशासन और बलिदान की मूरत है। शुरुआत से ही, मुझे यह कहानी पसंद आई, जो धमाकेदार होने के साथ–साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली है। रिश्तों को करीब से दिखाने वाली इस फिल्म का सिनेमाई स्तर भी अव्वल दर्जे का है। प्राइम वीडियो, एकेएफसीएन और सुरेश त्रिवेणी ने बेहतरीन क्रिएटिव टीम के सहयोग से इस फिल्म कि दुनिया का निर्माण किया। सुपरस्टार और दमदार एक्टर अनिल कपूर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में, दर्शकों को प्राइम वीडियो पर ऐसा बेमिसाल सिनेमाई अनुभव मिलने वाला है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा।

डायबिटीज रोगियों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए व्हाइट ब्रेड, हो सकती है ये बीमारियां !

डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी का जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। शोध के अनुसार, आज के समय में भारत में करीबन 77 मिलियन लोग डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी से जुझ रहे हैं। इन लोगों में 12.1 मिलियन लोग ऐसे ही जिनकी उम्र 65 साल से कम है।

यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है लेकिन स्वस्थ खान–पान और हैल्दी डाइट के साथ आप रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। डायबिटीज के रोगियों को अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या वह सफेद ब्रेड का सेवन कर सकते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या डायबिटीज के रोगी सफेद ब्रेड खा सकते हैं...

क्या डायबिटीज रोगियों को खानी चाहिए सफेद ब्रेड?

एक्सपर्ट्स के अनुसार डायबिटीज के मरीजों को संतुलित आहार का सेवन ही करना चाहिए, ताकि शरीर में ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित किया जा सके। सफेद ब्रेड का सेवन करने से इन लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है क्योंकि सफेद ब्रेड में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर में फैट और शुगर का स्तर बढ़ा सकता है जिसके कारण कई और बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है।

आइए आपको बताते हैं कि डायबिटीज रोगियों को सफेद ब्रेड खाने से क्या नुकसान होंगे...

बढ़ेगा हृदय रोगों का खतरा

सफेद ब्रेड का सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों में हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो मरीजों का जोखिम बढ़ सकता है। रिसर्च में भी यह बात साबित हो चुकी है कि सफेद ब्रेड का सेवन करने से डायबिटीज मरीजों में हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है।

पाचन हो सकता है प्रभावित

सफेद ब्रेड को बनाने के लिए मैदे का प्रयोग किया जाता है। जिसके कारण इसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में मैदे का इस्तेमाल करने से पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। कब्ज, पेट में दर्द और उल्टी जैसी परेशानियां सफेद ब्रेड खाने से बढ़ सकती है।

बढ़ेगी ब्लड शुगर

सफेद ब्रेड को तैयार करने के लिए काफी ज्यादा प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में प्रोसेस्ड होने के कारण यह शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा सकती है। ऐसे में ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज मरीजों को और भी अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बढ़ सकता है वजन

सफेद ब्रेड में बाकी ब्रेड की तुलना में कैलोरी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कैलोरी ज्यादा मात्रा में होने के कारण सफेद ब्रेड खाने से वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि डायबिटीज रोगियों का वजन बढ़ जाए तो शुगर का स्तर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डायबिटीज में बढ़ते वजन के कारण हृदय रोग और हृदय स्ट्रोक जैसी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है।

किन लोगों को नहीं रखना चाहिए महाशिवरात्रि का व्रत ? जानें क्या करें अगर नहीं रख पा रहे उपवास

इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाला यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु विधि–विधान से पूजा–अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण कर भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सच्चे मन से की गई आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि का व्रत आमतौर पर अगले दिन यानी 16 फरवरी 2026 को पारण के साथ संपन्न किया जाएगा। हालांकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हर व्रत सभी के लिए अनिवार्य नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थितियों में व्रत रखने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं किन लोगों को महाशिवरात्रि का कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए और वे उपवास की जगह क्या उपाय कर सकते हैं।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक भूखे रहने या निर्जला व्रत रखने से मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में कठोर या निर्जला व्रत रखने से बचना चाहिए।

क्या करें?

डॉक्टर की सलाह से फलाहार या हल्का व्रत रखा जा सकता है।

बिना नमक का भोजन या फल–दूध का सेवन किया जा सकता है।

शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर, ओमः नमः शिवाय" का जाप करने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है।

मासिक धर्म के दौरान महिलाएं

परंपरागत मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा सामग्री या मूर्ति को स्पर्श नहीं करतीं।

क्या करें?

मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करें।

शिव मंत्रों का जाप करें।

रात्रि में शिव कथा सुनें या पढ़ें।

मानसिक भक्ति और श्रद्धा से किया गया स्मरण भी उतना ही फलदायी माना जाता है।

गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग

हृदय रोग, डायबिटीज, उच्च या निम्न रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए लंबे समय तक भूखा रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

क्या करें?

चिकित्सक की सलाह के बिना निर्जला व्रत न रखें।

हल्का फलाहार या नियमित भोजन लेकर भी व्रत का संकल्प कर सकते हैं।

शिव मंदिर में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

दान–पुण्य करें और जरूरतमंदों की सहायता करें।

बुजुर्ग श्रद्धालु

अधिक आयु में शरीर की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में कठोर उपवास से कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है।

क्या करें?

अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें।

दिनभर शिव नाम का जप करें।

गरीबों को भोजन, वस्त्र या फल दान करें।

शिव–पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें।

बिना व्रत रखे ऐसे पाएं शिव कृपा

महाशिवरात्रि पर केवल उपवास ही जरूरी नहीं है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है।

शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें।

"ओमः नमः शिवाय" या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करें।

रात्रि जागरण और भजन–कीर्तन करें।

दान–पुण्य और सेवा कार्य करें।

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, भगवान शिव सरल और भोले स्वभाव के देवता हैं। वे श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होते हैं, न कि केवल कठोर व्रत से। महाशिवरात्रि 2026 का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए व्रत रखने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे, तो भक्ति, मंत्र–जाप और दान–पुण्य के माध्यम से भी पूर्ण पूजा फल प्राप्त किया जा सकता है।

गरुड़ पुराण के नियमः आपकी गरीबी की वजह आपकी रसोई हो सकती है

भारतीय संस्कृति में रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं मानी जाती, बल्कि इसे घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि रसोई घर की सेहत, सुख–शांति और समृद्धि से सी ो तौर पर जुड़ी होती है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी रसोई से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता ला सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर रसोई को सही तरीके से संभाला जाए और कुछ धार्मिक नियमों का पालन किया जाए, तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए आसान भाषा में जानते हैं ये जरूरी बातें।

रसोई की पूजा से करें शुरुआत

गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस स्थान पर भोजन बनाया जाता है, वह बहुत पवित्र होता है। इसलिए खाना बनाने से पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। चूल्हा या गैस जलाने से पहले एक छोटी–सी प्रार्थना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भोजन तैयार होने के बाद पहला ग्रास (कण) भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। कई घरों में इसे थाली के एक कोने में रखकर या मानसिक रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होने की मान्यता है।

रसोई में साफ–सफाई का रखें विशेष ध्यान

शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही निवास करती हैं। इसलिए रसोई की साफ–सफाई केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी जरूरी है। रोजाना किचन की सफाई करें, काउंटर साफ रखें, बर्तन समय पर धोएं और फर्श को साफ रखें। गंदगी, बिखरे हुए सामान और जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। एक साफ और व्यवस्थित रसोई घर में सुख–शांति और धन को आकर्षित करती है।

तुलसी से जुड़े नियमों का करें पालन

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। कई घरों में तुलसी को रसोई या घर के पास लगाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। इसे धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। रविवार, एकादशी, संक्रांति या शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों और समय में तुलसी विश्राम करती हैं। रोज सुबह खासकर सूर्योदय के समय तुलसी को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख–शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी के पौधे के आसपास साफ–सफाई रखें। उसके सामने जूते–चप्पल न रखें और आसपास कूड़ा न फेंकें। ऐसा करने से आध्यात्मिक पुण्य में कमी आती है और समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

रसोई को मानें घर की किस्मत का केंद्र

गरुड़ पुराण के अनुसार, रसोई घर की ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। यहां से पूरे परिवार की सेहत और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। इसलिए रसोई में क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचना चाहिए। खाना बनाते समय सकारात्मक सोच रखें और प्रेम भाव से भोजन तैयार करें। माना जाता है कि जैसा भाव होगा, वैसी ही ऊर्जा भोजन में शामिल होती है और वही ऊर्जा परिवार के सदस्यों तक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार, रसोई घर केवल भोजन पकाने का स्थान नहीं, बल्कि समृद्धि और सुख का आधार है। अगर आप रोजमर्रा की छोटी–छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे प्रार्थना करना, साफ–सफाई रखना और तुलसी के नियमों का पालन करना, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बनी रह सकती है।

स्नैक में ट्राई करें टेस्टी पुदीना कचौरी, एक बार खाएंगे तो बार-बार मांगेंगे

गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। इस मौसम में बॉडी को अंदर से ठंडा और तरोताजा रखने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पुदीना। पुदीना खाने के साथ–साथ हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। पुदीना को आपने पुदीना की चटनी, रायता, पराठा जैसे कई खाने में उपयोग किया होगा। लेकिन क्या कभी आपने पुदीना कचौरी का नाम सुना है। अगर नहीं, तो आज हम आपको इसकी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। पुदीना कचौरी को बनाने में आपको ज्यादा मेहनत और पैसे खर्च करने की जरुरत नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पुदीना पसंद है तो आपको भी पुदीना कचौरी बना के जरुर खानी चाहिए। आइए आपको बताते हैं इसकी आसाना रेसिपी...

सामग्री

आटा– 4 कप
पुदीना– 1 कप
जीरा– 1 चम्मच
हरी मिर्च– 2
बेकिंग सोडा– 2 चुटकी
नमक स्वादानुसार
तेल– 3 कप
अदरक– 1/2 चम्मच
धनिया पाउडर– 1/2 चम्मच
सौंफ पाउडर– 1/2 चम्मच
हींग– स्वादानुसार

विधि

1. सबसे पहले आप पुदीना के पत्तों को अच्छे से साफ कर लीजिए और इसे काट कर अलग रख लीजिए।

2. अब एक बर्तन में आटा लें और उसमें पुदीना के साथ जीरा, बेकिंग सोडा, हरी मिर्च और नमक डालकर आटा को गूंथ लीजिए।

3. अब इसे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए ढककर अलग रख दीजिए।

4. 12 मिनट बाद आटे की छोटी–छोटी लोइयां बनाकर उन्हें कचौरी के आकार में बेल लीजिए।

5. एक कढ़ाही में तेल गरम करें और इन्हें अच्छे से तल लीजिए।

6. आपकी पुदीना की कचौरी तैयार है। अब इसे अचार या चटनी के साथ किसी प्लेट में निकाल कर गर्मा–गर्म सर्व करें।

संक्षिप्त

एसआईटी को नहीं मिला प्रताड़ना का कोई सबूत, माना जा रहा तनाव के कारण गई उद्योगपति की जान

नई दिल्ली,एजेंसी। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की मौत की जांच कर रही विशेष जांच टीम को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। इससे यह साबित हो कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित या दबाव में लिया था। जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार रॉय गहरे कारोबारी तनाव से जूझ रहे थे, जो कथित तौर पर आत्महत्या की मुख्य वजह बन सकता है। एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि 31 जनवरी को बंगलूरू स्थित अपने दफ्तर में खुद को गोली मारने वाले रॉय से उस दिन आयकर अधिकारियों ने कोई पूछताछ नहीं की थी। जांच में अब तक ऐसा कोई ठोस आधार भी नहीं मिला है, जिससे यह संकेत मिले कि टैक्स अधिकारियों ने उन पर अनुचित दबाव डाला हो। सूत्रों के अनुसार आयकर अधिकारियों द्वारा धमकी या जबरन दबाव डालने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। रॉय अन्य अनसुलझे मुद्दों को लेकर परेशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हाल के महीनों में रॉय ने मानसिक तनाव के लिए इलाज क्यों कराया था। उनके मानसिक हालात को समझने के लिए एसआईटी ने कोच्चि के तीन करीबी मित्रों के बयान दर्ज किए हैं, जिनसे उन्होंने मौत से पहले के दिनों में लंबी फोन बातचीत की थी। बताया गया है कि इन मित्रों के साथ उनका निजी, न कि कारोबारी, संबंध था। जांच के तहत उन दो यूट्यूबर्स से भी जानकारी मांगी गई है, जिन्होंने कंफिडेंट ग्रुप के लिए प्रचार सामग्री तैयार की थी। इससे पहले कंपनी के कुछ कारोबारी साझेदारों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस अब रॉय के वित्तीय लेन–देन की विस्तृत जांच की तैयारी में है। उनकी कंपनियों के ऑडिट दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल पर चर्चा, कानून में बदलाव का मकसद क्या?

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 को 28 सितंबर 2020 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कोड के लागू होने से पहले ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926य औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946य और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 प्रभावी थे। इन तीनों पुराने कानूनों को समाहित कर एकीकृत रूप में यह नया कोड लाया गया। उन्होंने कहा कि नए कोड के लागू होने के साथ ही सरकार को इन पूर्ववर्ती अधिनियमों को निरस्त (रिपील) करने का अधिकार प्राप्त हुआ था और सरकार ने उन्हें निरस्त भी कर दिया है। अब उद्देश्य यह है कि इस संबंध में एक छोटा–सा संशोधन किया जाए, ताकि यह प्रावधान स्पष्ट रूप से अधिनियम का हिस्सा बन सके और किसी प्रकार की कानूनी अस्पष्टता न रहे। उन्होंने सदन से अनुरोध किया कि इस संशोधन को स्वीकार कर पारित किया जाए, ताकि कानून की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके।

पत्नी प्रिया सचदेवा ने हाईकोर्ट में 20 करोड़ की मानहानि का केस किया

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रिया सचदेवा कपूर ने अपनी ननद मंधिरा कपूर स्मिथ और एक पॉडकास्टर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 20 करोड़ रुपये का सिविल मानहानि मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पॉडकास्ट, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी प्रिया सचदेवा कपूर ने उन्हीं कथित बयानों को लेकर मंधिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। यह कानूनी विवाद आरके फैमिली ट्रस्ट और संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद के बीच सामने आया है, जो पहले से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। प्रिया ने दावा किया कि संजय ने 2025 में बनाई गई वसीयत में अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति उन्हें सौंपी है। इस दावे को करिश्मा कपूर (अपने बच्चों की ओर से) और रानी कपूर ने चुनौती दी है और वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। रानी कपूर ने कोर्ट में त्ज्ञ फैमिली ट्रस्ट को अवैध घोषित करने तथा लगभग घ्28 करोड़ के अंतरिम डिविडेंड को प्रिया को हस्तांतरित न करने की मांग उठाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की याचिकाओं पर नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 23 मार्च तक तय की है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों को सलाह दी कि वे पारिवारिक विवाद को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के बजाय मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। अदालत ने कहा कि विवाद में सार्वजनिक रूप से निजी बातें उठाकर 'गंदे कपड़े सरेआम धोने' जैसी स्थिति पैदा हो रही है और इसे रोका जाना चाहिए।

15 फरवरी को आमने–सामने होंगे पांच एशियाई क्रिकेट बोर्ड प्रमुख

दुबई,एजेंसी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चले विवाद के बाद अब आईसीसी डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रहा है। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत–पाकिस्तान मुकाबले के दौरान एशिया की पांच बड़ी क्रिकेट ताकतों के प्रमुखों को एक साथ बैठाकर बातचीत कराने की योजना बनाई गई है। मकसद साफ है, तनाव कम करना और क्रिकेट कूटनीति के जरिए रिश्तों को पटरी पर लाना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के प्रमुख अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखने के लिए कोलंबो जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि पिछले कुछ सप्ताह से चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ उनके संबंध सुधरेंगे।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने स्थानीय अखबार 'प्रथम आलो' को बताया कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की तरफ से निमंत्रण मिला है। अमीनुल ने कहा, आईसीसी के प्रमुख हितधारक पांच एशियाई देश हैं और वह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने मैच के लिए सभी पांच एशियाई देशों के प्रतिनिधि एक साथ स्टेडियम में मौजूद रहें, मैच देखें और एक–दूसरे से बात करें। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एशिया के आईसीसी में महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अमीनुल के मुताबिक, वर्ल्ड कप से ठीक पहले तीनों देशों के रिश्ते बेहद तल्ख हो गए थे। इस्लाम से पूछा गया कि क्या इस बैठक से बीसीसीआई के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधा खत्म करने में मदद मिलेगी, उन्होंने कहा, आप इसे कुछ इसी तरह मान सकते हैं।

आईसीसी की यह पहल ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच के बहिष्कार की अपनी पुरानी घोषणा से आखिरी वक्त में पलटी मारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिकेट कूटनीति और आर्थिक असर को देखते हुए यह फैसला बदला गया। अमीनुल इस्लाम का दावा है कि पाकिस्तान बहिष्कार के लिए तैयार था और उन्हें खुद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को समझाना पड़ा। भारत–पाकिस्तान मैच को दुनिया के सबसे कमाऊ मुकाबलों में गिना जाता है, जिससे करीब 250 मिलियन डॉलर के प्रसारण राजस्व की बात होती है। बांग्लादेश ने दलील दी कि अगर यह मैच नहीं हुआ, तो नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे क्रिकेट जगत का होगा।

बीसीबी प्रमुख ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप से पूरी तरह हटने की धमकी तक दे दी थी। अगर ऐसा होता और बांग्लादेश भी किनारे रहता, तो टूर्नामेंट की सबसे कीमती टक्करें खतरे में पड़ जातीं। इससे ब्रॉडकास्ट डील और कमर्शियल समझौतों पर दूरगामी असर पड़ सकता था। आखिरकार नौ फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने रुख बदला। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त देशों की अपील और बहुपक्षीय बातचीत के नतीजों ने फैसले को प्रभावित किया। बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई जैसे देशों के आग्रह का भी जिक्र हुआ।

बीसीसीआई और बीसीबी के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय बोर्ड ने कुछ अज्ञात परिस्थितियों के चलते बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल अनुबंध से बाहर करने का आदेश दिया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह कदम बांग्लादेश में हुई राजनीतिक हिंसा से प्रेरित था जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए विश्व कप मैचों के लिए भारत आने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी ने बांग्लादेश की चिंताओं को खारिज कर दिया था। बांग्लादेश हालांकि अपने रुख पर कायम रहा इसके बाद उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी गई। इस्लाम ने कहा कि बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार करेगा जिससे आईसीसी की तरफ से उन्हें मिले आश्वासनों को अंतिम रूप दे दिया जाए। उन्होंने कहा, श्हम एक समझौता भी करेंगे। यह एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) जैसा दस्तावेज होगा, ताकि कोई अनिश्चितता न रहे। आईसीसी के साथ (समझौता ज्ञापन तैयार करने के संबंध में) चर्चा लगभग अंतिम पड़ाव पर है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कोलंबो में होने वाली यह हाई–प्रोफाइल मुलाकात सिर्फ औपचारिकता रहती है या वाकई रिश्तों में नई शुरुआत का रास्ता खोलती है। भारत–पाकिस्तान मैच हमेशा भावनाओं का ज्वार लेकर आता है।

बस खेलना नहीं, जीतना है! रोहित का मिशन 2027 वर्ल्ड कप, क्या अधूरा सपना पूरा कर पाएंगे हिटमैन ?

मुंबई,एजेंसी। रोहित शर्मा ने कहा है कि वह 2027 वनडे विश्व कप सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि देश के लिए जीतने उतरना चाहते हैं। 2023 फाइनल की हार उनकी प्रेरणा है। फिटनेस पर मेहनत और अनुभव के दम पर वह अधूरा सपना पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2024 और चौंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताने वाले रोहित शर्मा के दिल में वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल में हारने का दर्द अब भी चुभता है। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार ने उस ट्रॉफी को उनके लिए अधूरा सपना बना दिया है। अब रोहित खुलकर कह रहे हैं कि अगला लक्ष्य सिर्फ खेलना नहीं, जीतना है। आईसीसी के एक कार्यक्रम में रोहित ने साफ कर दिया कि 2027 उनके करियर का बड़ा मिशन होगा। उन्होंने कहा, मैं 50 ओवर का विश्व कप देखते हुए बड़ा हुआ हूं। वही सबसे बड़ा मंच था। मैं सच में वह ट्रॉफी चाहता हूं और उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं वहां जाकर अपने देश के लिए विश्व कप जीतना चाहता हूं। यह बयान बताता है कि रोहित के लिए यह सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, बल्कि अधूरी कहानी का अगला अध्याय है। टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद कई लोगों ने मान लिया था कि 2027 तक रोहित का सफर मुश्किल होगा, लेकिन पिछले महीनों में उन्होंने फिटनेस पर जबरदस्त काम किया, वजन घटाया और मैदान पर नई ऊर्जा के साथ लौटे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भले रन नहीं बने, मगर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने फिर याद दिलाया कि बड़े मंच के खिलाड़ी अब भी जिंदा हैं। रोहित सिर्फ इरादों से नहीं, आंकड़ों से भी दमदार हैं। उन्होंने 282 वनडे में 11,577 रन बनाए हैं और इनमें 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं। ये नंबर बताते हैं कि वह क्यों अब भी दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अगर फिटनेस साथ देती है, तो 2027 में उनका अनुभव टीम के लिए सोना साबित हो सकता है। रोहित की बातें साफ इशारा करती हैं कि तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। लक्ष्य सिर्फ हिस्सा लेना नहीं, बल्कि ट्रॉफी उठाकर 2023 की टीस मिटाना है।

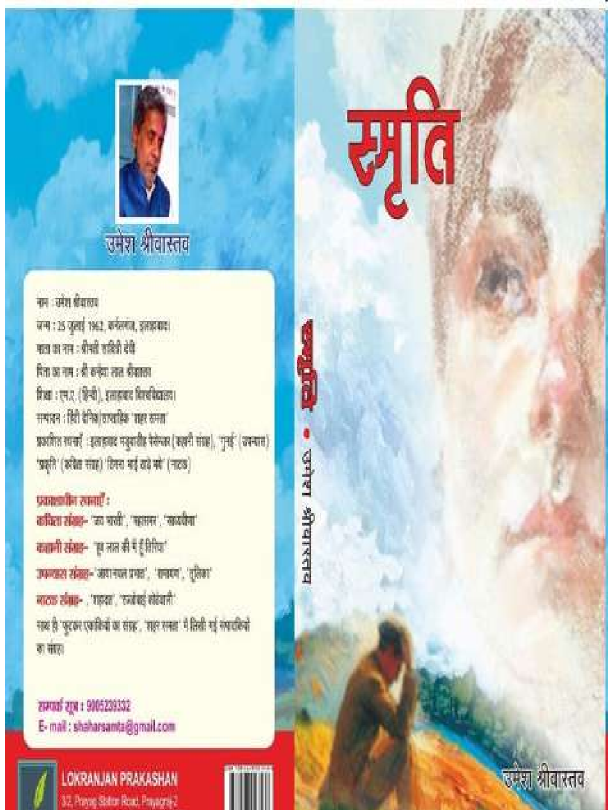

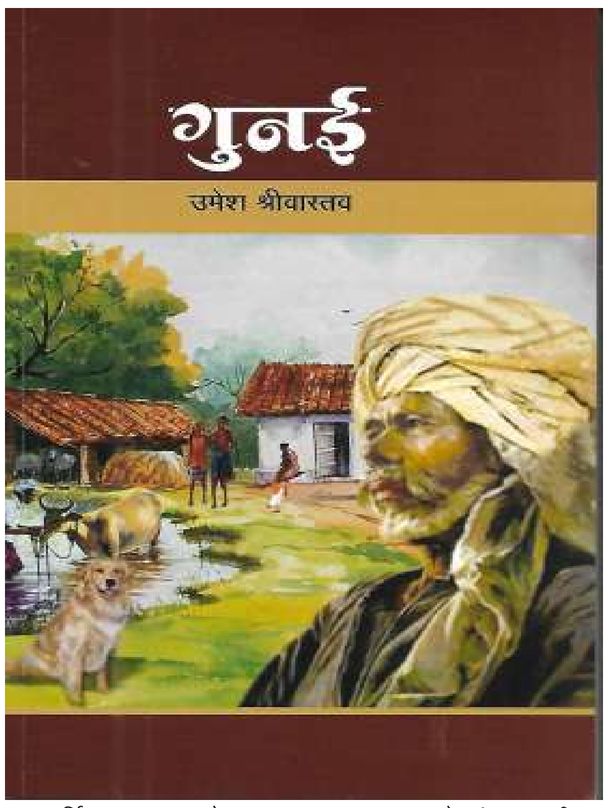

चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

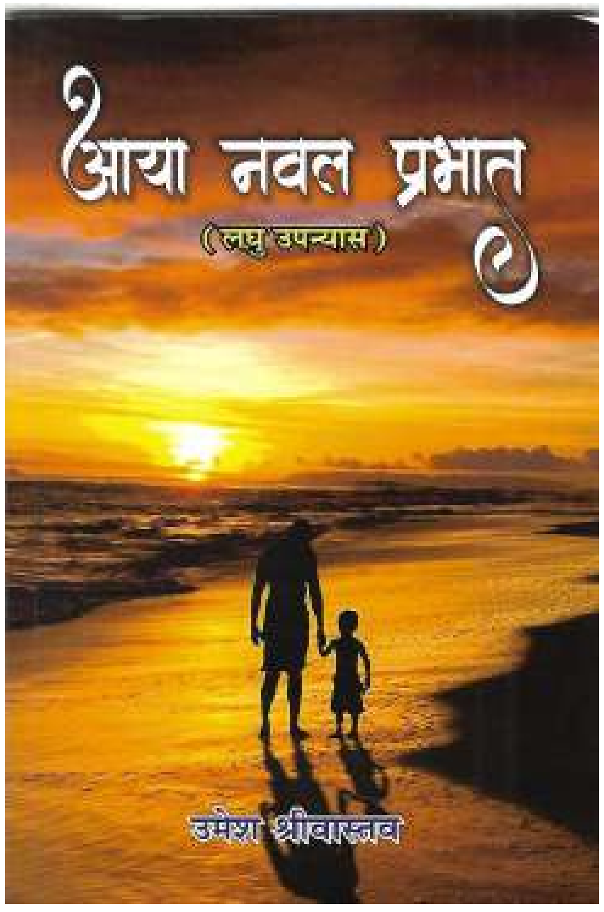

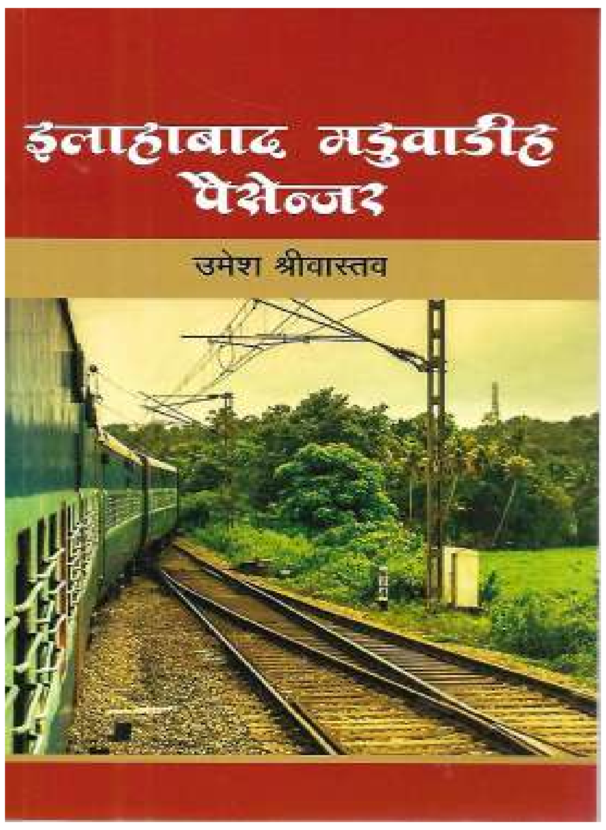

समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

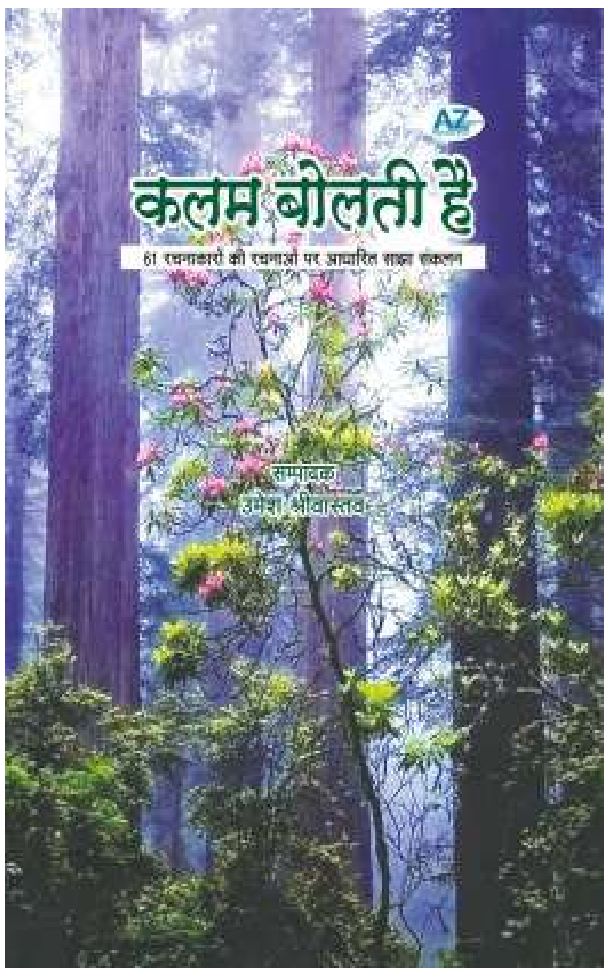

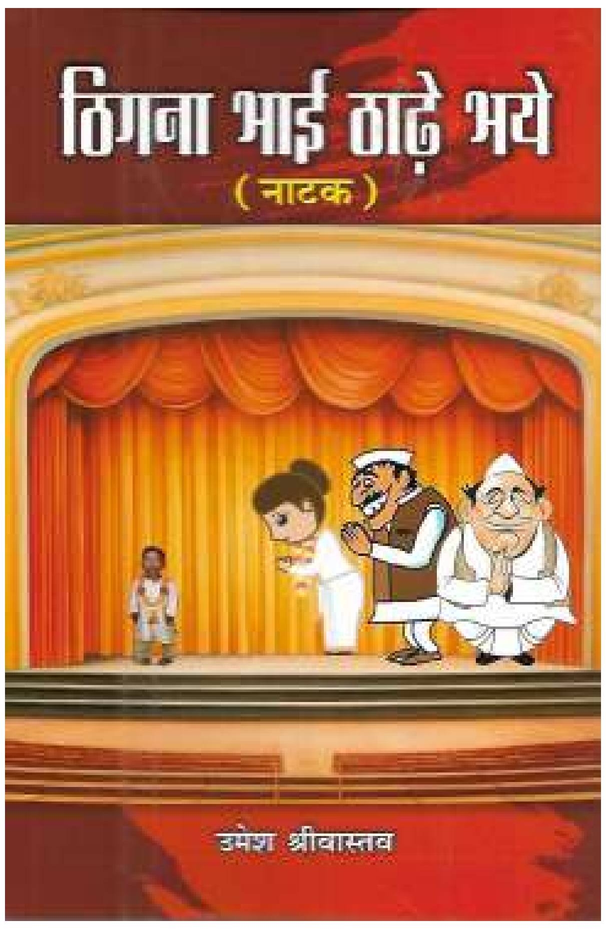

ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

संक्षिप्त

अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा ईरान, विदेश मंत्री अराघची बोले- हम बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर चल रही बातचीत के बीच सख्त और साफ संदेश दिया है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है लेकिन हाल की घटनाओं ने अमेरिका पर भरोसा कमजोर किया है। उनके बयान से साफ है कि वार्ता और तनाव दोनों साथ–साथ चल रहे हैं। एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा कि ईरान अब भी अमेरिका के साथ बातचीत चाहता है, लेकिन पूरा भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पिछले साल जून में जब बातचीत चल रही थी, उसी दौरान हमला हुआ, जो ईरान के लिए खराब अनुभव रहा। उनके मुताबिक सैन्य हमले और धमकियां किसी देश की तकनीकी प्रगति को नहीं रोक सकतीं। इसलिए स्थायी समाधान सिर्फ कूटनीति से ही निकलेगा। अराघची ने दोहराया कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और यह देश का संप्रभु अधिकार है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 5 प्रतिशत से कम संवर्धन की जरूरत होती है। तेहरान रिसर्च रिएक्टर के लिए 20 प्रतिशत तक संवर्धन का ईंधन चाहिए, जिसका उपयोग कैंसर इलाज के लिए मेडिकल आइसोटोप बनाने में होता है। उन्होंने कहा कि प्रतिशत से ज्यादा जरूरी यह है कि कार्यक्रम का मकसद शांतिपूर्ण है। ईरान इस बात की गारंटी देने को भी तैयार है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के साथ सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बात करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों पर कोई बातचीत नहीं होगी। अराघची ने कहा कि ये मांगें बिल्कुल स्वीकार नहीं हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान से होने वाली किसी भी डील में मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय संगठनों का मुद्दा भी शामिल हो। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर बातचीत नाकाम होती है और नया हमला होता है तो ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल इजराइल और अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान की सैन्य तैयारी संख्या और गुणवत्ता दोनों में बढ़ी है। उन्होंने नेतन्याहू को युद्ध भड़काने वाला नेता बताया और आरोप लगाया कि वह अमेरिका को बड़े टकराव में खींचना चाहते हैं। अराघची ने चेतावनी दी कि दोबारा हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान परमाणु समझौता चाहता है। उन्होंने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन चेतावनी दी कि डील नहीं होने पर बहुत सख्त परिणाम होंगे। ट्रंप परमाणु हथियार और मिसाइल रोकने वाली सख्त डील चाहते हैं। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर क्षेत्रीय मुद्दों और ईरान वार्ता पर चर्चा की। साफ है कि कूटनीति जारी है, लेकिन अविश्वास और खतरा दोनों बने हुए हैं।

मानसिक शिकायतों से जूझ रही थी हमलावर युवती, घर पर मां और सौतेले भाई को भी उतारा मौत के घाट

ब्रिटिश कोलंबिया , एजेंसी। पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टंबलर रिज कस्बे में मंगलवार को एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 10 लोगों की मौत हो गई। यह हाल के वर्षों में देश की सबसे घातक सामूहिक हिंसा

की घटनाओं में से एक है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के अनुसार, छह लोग स्कूल के भीतर मृत पाए गए, दो शव एक संबंधित आवास से बरामद हुए और एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। कम से कम दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि लगभग 25 लोगों का इलाज गैर–गंभीर चोटों के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने कनाडा में एक स्कूल में हुई गोलीबारी के संदिग्ध की पहचान 18 वर्षीय युवती के रूप में की है। युवती को लेकर पहले भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें दर्ज की गई थीं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के उप आयुक्त ड्वेन मैकडॉनल्ड ने बुधवार को कहा कि हमलावर वैन रूटसलार का मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास था। उन्होंने बताया कि संदिग्ध हमलावर की मां और सौतेले भाई स्कूल के पास एक घर में मृत पाए गए थे। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर भी स्कूल परिसर में मृत मिला और प्रारंभिक जांच में मामला जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल किसी अन्य संदिग्ध या खतरे की आशंका नहीं है। घटना के दौरान स्कूल को लॉकडाउन कर दिया गया था। स्थानीय पादरी जॉर्ज रोवे ने कहा कि कई अभिभावक सामुदायिक केंद्र में अपने बच्चों की खबर का इंतजार करते रहे।

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र
शहर समता हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र
मोबाईल नम्बर 9190052 39332
.919450482227

'नए बांग्लादेश का जन्मदिन', मतदान के बाद यूनुस ने आज के दिन को बताया खास, जनता से बड़ी अपील

ढाका, एजेंसी। करीब 18 महीनों के अंतराल के बाद बांग्लादेश में चुनावी लोकतंत्र फिर से पटरी पर लौटता दिख रहा है। 13वें संसदीय चुनाव के साथ अंतरिम शासन के बाद जनता को नई सरकार चुनने का मौका मिला है।राजनीतिक उथल–पुथल, विरोध प्रदर्शनों और अस्थिरता के बीच यह मतदान देश की लोकतांत्रिक नींव को फिर से मजबूत करने की अहम कड़ी माना जा रहा है। ऐसे में जारी मतदान बीच देश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज में अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने इस दिन को बहुत खुशी का दिन बताया और इसे नए बांग्लादेश का जन्मदिन कहा। इस दौरान यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और साथ ही राष्ट्रीय जनमत संग्रह में भी भाग लें। बता दें कि मतदान से एक दिन पहले देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने इस चुनाव को देश के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया था। उन्होंने कहा था कि यह चुनाव और जनमत संग्रह बांग्लादेश के इतिहास में एक अनोखा और महत्वपूर्ण अध्याय माना जाएगा। बता दें कि ये चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल लंबे शासन के खत्म होने के करीब 18 महीने बाद हो रहे हैं। शेख हसीना को देशभर में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद से देश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है। हालांकि, यूनुस सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इतना ही नहीं कट्टर इस्लामी संगठनों के प्रभाव में बढ़ोतरी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताई गई है। कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि इस दौरान कानून–व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है और ठोस सुधार नहीं हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस चुनाव में लगभग 12 करोड़ 77 लाख (127.7 मिलियन) पंजीकृत मतदाता मतदान कर सकते हैं। इनमें करीब 6 करोड़ 28 लाख महिलाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि पहली बार वोट देने के लिए पंजीकरण कराने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। लगभग 27 लाख नई महिला मतदाता हैं, जबकि नए पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 18.7 लाख है। हालांकि मतदाताओं में महिलाओं की भागीदारी बड़ी है, लेकिन चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है। कुल उम्मीदवारों में से केवल 83 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं, जो कुल उम्मीदवारों का लगभग 4 प्रतिशत है। इनमें 63 महिलाओं को राजनीतिक दलों ने टिकट दिया है, जबकि 20 महिलाएं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए देशभर में लगभग 9 लाख 58 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील और जोखिम वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, कानून–व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख से अधिक सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं। जहां एक ओर कई राजनीतिक दल सरकार बनाने का भरोसा जता रहे हैं, वहीं उन्होंने यह भी माना है कि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इस बीच, पूर्व सत्ताधारी दल अवामी लीग ने इन चुनावों को दिखावा बताया है। पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह बांग्लादेश को टूटने से बचाए। अवामी लीग का कहना है कि यह चुनाव केवल उनकी पार्टी को किनारे करने के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी दलों को बाहर रखने की कोशिश है जो कट्टर विचारधारा का विरोध करते हैं और उदार बांग्लादेश की वकालत करते हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता में बदलाव से कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिल सकता है। कुल मिलाकर, बांग्लादेश के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मतदान कितना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहता है, और आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।

भारत के लिए कितने अहम बांग्लादेश के चुनाव: नतीजों से कैसे पड़ सकता है प्रभाव, किस पार्टी का क्या रुख?

बांग्लादेश, एजेंसी। बांग्लादेश में आज आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव के साथ ही यह तय हो गया है कि अब कुछ ही दिनों में जब भारत अपने रिश्तों को लेकर बांग्लादेश से संपर्क में होगा, तब उसकी बात मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार नहीं, बल्कि एक स्थायी–चुनी हुई सरकार से होगी। ऐसे में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अब भारत के लिए अगली सरकार से चर्चा की रणनीति काफी अहम होने वाली है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर बांग्लादेश के चुनाव भारत के लिए कितने अहम हैं? किस तरह इस चुनाव के नतीजे दोनों देशों के रिश्तों को आगे प्रभावित कर सकते हैं? इसके अलावा इन चुनावों के मुद्दे क्या हैं? इन पर और भारत को लेकर किस पार्टी का क्या रुख है? आइये जानते हैं.... 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में उतार–चढ़ाव देखे गए हैं। हालांकि, 21वीं सदी के अधिकतर हिस्से में भारत–बांग्लादेश परस्पर सहयोगी रहे हैं। शेख हसीना के नेतृत्व में (2009–2024) के बीच बांग्लादेश सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर में फैले उग्रवाद को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। खासकर उल्फा और एनडीएफबी जैसे संगठन, जो कभी बांग्लादेश से सप्लाई होने वाले हथियारों के जरिए भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, उनकी गतिविधियों को रोकने में खासी सफलता हासिल हुई। बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के कूटनीतिक सहयोग में किसी तरह का बदलाव भारत के उत्तर में स्थित क्षेत्र के लिए सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। बांग्लादेश में चार पार्टियां मुख्य तौर पर मुकाबले में हैं। हालांकि, इसमें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग शामिल नहीं है। दरअसल, बीते साल जब हसीना के शासन के खिलाफ छात्र आंदोलन हिंसक हो गया तब वे बांग्लादेश छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गईं। इसके बाद बांग्लादेश में बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में न सिर्फ आवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया, बल्कि शेख हसीना के खिलाफ उनकी गैरमौजूदगी में कई केस भी चलवाए। इनमें से एक केस का फैसला इसी साल नवंबर में आया, जिसमें अपदस्थ पीएम को मौत की सजा सुनाई गई। चूंकि शेख हसीना भारत में हैं, इसलिए उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश में यह भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है।

बांग्लादेश में इन दो दलों के बीच मुख्य मुकाबला, सभी का भारत से रिश्ते सुधारने पर जोर

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। वोटिंग की शुरुआत सुबह सात बजे से होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच कराए जा रहे आम चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और कभी इसकी सहयोगी रही जमात– ए–इस्लामी के बीच मुख्य मुकाबला है। दोनों ही दलों ने सत्ता में आने पर भारत के साथ रिश्ते सुधारने और मजबूत करने के साथ पर जोर दिया है। चुनाव पूर्व जनमत सर्वेक्षणों में बीएनपी सत्ता में आती दिख रही है, जिसके प्रमुख तारिक रहमान, जो ब्रिटेन में 17 वर्षों के निर्वासन के बाद वापस लौटे हैं, अगली सरकार बनाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के साथ रिश्तों पर बीएनपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जीबा अमीना खान ने बुधवार को कहा कि वह सीमा मुद्दों पर शीघ्र समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के साथ पड़ोसी संबंध चाहती हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोसी हैं। हम दोस्त हैं। हमें दोस्त रहना चाहिए। हमारी सीमा बहुत लंबी है, इसलिए हमें एक–दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हमें भारत से कोई दुश्मनी क्यों होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं को समझते हुए भारत को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के तरीके खोजने चाहिए। अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, अमीना खान ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों का सवाल नहीं है। वे हमारे नागरिक हैं। छात्र आंदोलन के चलते 15 साल से सत्ता में रहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पिछले साल अगस्त में गिर गई थी। हसीना सरकार के पतन के बाद यह पहला आम चुनाव है और राजनीतिक वजहों से हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। बांग्लादेश जमात–ए–इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी भारत के साथ मजबूत, सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, हम अपने पड़ोसी देशों और विश्वभर के मित्रों के साथ सकारात्मक संबंध चाहते हैं। भारत हमारा निकटतम पड़ोसी है और यह हमारी प्राथमिकता बना रहेगा। हमारा लक्ष्य संघर्ष पैदा करना नहीं, बल्कि विकास और शांति के लिए साझेदारी बनाना है। आपसी सम्मान और विश्वास आवश्यक हैं। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कहा, उनका धर्म कोई भी हो, वे सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में ढाका समेत पूरे देश में स्कूलों और सार्वजनिक इमारतों को पुरानी परंपरा के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में बदला जा रहा है। चुनाव आयोग का परामर्श मानते हुए, अभियान में सिर्फ ब्लैक–एंड–व्हाइट बैनर व पोस्टर दिखाए गए। उम्मीदवारों ने इन्हें सीधे दीवारों पर लगाने के बजाय रस्सी से टांगा, जो चुनाव कानूनों के तहत गलत है। इससे ढाका की सड़कें एक खास मोनोक्रोमैटिक लुक दे रही हैं। देश की 300 सीटों में से 299 पर 12.77 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट देंगे, एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के चलते वोटिंग टाल दी गई है। बांग्लादेश में मतदान से ठीक पहले देश में हलचल है। दरअसल, चुनाव से कुछ ही घंटे पहले विश्व बैंक ने ढाका के लिए पैसों की बौछार कर दी है। उसने 37 करोड़ डॉलर, यानी करीब 33.51 अरब रुपये की फंडिंग की, जो ढाका की गंदी नदियों और नालों को साफ करने, सीवर प्रणाली सुधारने और कचरा प्रबंधन मजबूत करने के लिए है। इतनी बड़ी फंडिंग की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञ इसे महज संयोग न मानकर एक बड़ी योजना मान रहे हैं, ताकि वोटर लुभाए जा सकें।

कैटी पेरी ने ट्रूडो के साथ साझा की तस्वीरें: निजी पलों की झलक ने फैंस को चौंकाया, डेटिंग की अटकलें तेज

ओटावा, एजेंसी। पॉप स्टार कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार

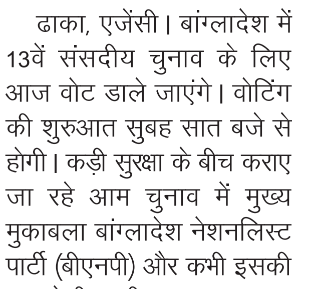

फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए सर्दियों के फोटो एल्बम ने दोनों के रिश्ते को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बर्फ से ढकी वादियों, स्कीइंग और साथ बिताए निजी पलों की तस्वीरों को लेकर फैंस कई तरह के कयास लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर इंटरनेट पर तेज प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कैटी पेरी ने एक विंटर थीम वाला फोटो कैरोसेल शेयर किया, जिसमें वह और जस्टिन ट्रूडो साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दोनों काले कपड़ों में बर्फीले पहाड़ों के बीच दिखते हैं। कुछ फोटो में स्कीइंग, कुछ में साथ खाना खाते और कुछ में सेल्फी लेते पल शामिल हैं। पोस्ट के कैप्शन में प्यार और बदलाव की बात लिखी गई, जिसके बाद फैंस ने इसे उनके रिश्ते का सार्वजनिक संकेत माना। हालांकि दोनों की ओर से रिश्ते को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यूजर्स का कहना है कि अब यह रिश्ता केवल अफवाह नहीं बल्कि खुलकर सामने आ रहा है। पहले भी दोनों को साथ यात्रा करते और निजी मौकों पर साथ देखा गया था। नई तस्वीरों ने इन अटकलों को और मजबूत किया है। कई फैंस इसे क्यूट विंटर मोमेंट बता रहे हैं। दोनों को लेकर पहली बार चर्चा पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी, जब उन्हें मॉन्ट्रियल में साथ डिनर करते देखा गया था। उस समय दोनों ने इस मुलाकात पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की थी। बाद में अलग–अलग मौकों पर साथ दिखने से कयास बढ़े। दिसंबर में कैटी पेरी ने अपने सोशल मीडिया पर साथ के कुछ पल साझा किए, जिसके बाद चर्चा और तेज हो गई। इसे निजी रिश्ते के सार्वजनिक होने की दिशा में बड़ा संकेत माना गया।

एपस्टीन फाइल्स पर अमेरिका में बवाल: अटॉर्नी जनरल बॉन्डी पर नाम छिपाने का आरोप, न्याय विभाग पर उठे सवाल

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में कुख्यात कारोबारी और दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संसद की एक समिति की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल बॉन्डी पर आरोप लगा कि उन्होंने एपस्टीन के प्रभावशाली साथियों के नाम छिपाए। रिपब्लिकन सांसदों ने न्याय विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि कानून के बावजूद पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने बॉन्डी से सीधे सवाल किए। उन्होंने कहा कि एपस्टीन यौन तस्करी जांच से जुड़े दस्तावेजों में संभावित सह–साजिशकर्ताओं की सूची में अरबपति कारोबारी लेस्ली वेक्सनर का नाम काला कर छिपाया गया। मैसी ने इसे कानून का पालन न करना और बड़ी विफलता बताया। जवाब में बॉन्डी ने कहा कि वेक्सनर का नाम दूसरे जारी दस्तावेजों में मौजूद है और आपत्ति उठने के 40 मिनट के भीतर उसे बिना ढंके जारी कर दिया गया। संसदीय समिति के कई सदस्यों ने शिकायत की कि एपस्टीन फाइल्स में जरूरत से ज्यादा हिस्से काले किए गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जिस कानून के तहत फाइलें जारी करने को कहा था, उसमें सीमित छूट की अनुमति है, लेकिन न्याय विभाग ने उससे ज्यादा सामग्री छिपाई। पिछले महीने विभाग ने 30 लाख से ज्यादा पन्नों का अंतिम दस्तावेज सेट जारी किया, लेकिन उसमें भी कई नाम और हिस्से हटाए गए थे। बॉन्डी ने अपने बचाव में कहा कि सैकड़ों वकीलों की टीम ने कम समय में फाइलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग का मकसद पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखना है। अगर कहीं पीड़ितों के नाम सामने आए तो वह अनजाने में हुई गलती है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा करियर पीड़ितों के लिए लड़ते हुए बीता है और आगे भी ऐसा करती रहेंगी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कुछ सांसदों के सवालों को राजनीतिक नाटक भी बताया। एपस्टीन मामला फिर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उसका नाम कई बड़े और ताकतवर लोगों से जुड़ा रहा है। एपस्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई थी, जब वह यौन तस्करी के आरोपों में ट्रायल का इंतजार कर रहा था। एपस्टीन के साथ पुराने संबंधों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति क्वदंसक ज्तनउच का नाम भी पहले सुर्खियों में रहा है, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और संवेदनशील बन गया है। न्याय विभाग पर यह भी आरोप लग रहा है कि वह कुछ मामलों में सख्ती और कुछ में नरमी दिखा रहा है। सुनवाई ऐसे समय हुई जब न्याय विभाग की निष्पक्षता पर भी बहस चल रही है। आलोचकों का कहना है कि विभाग की स्वतंत्र जांच की परंपरा कमजोर हुई है और फैसलों में राजनीतिक असर दिख रहा है। हालांकि विभाग ने इन आरोपों को खारिज किया है।

तीन घंटे चली नेतन्याहू संग बैठक, खत्म होने पर ट्रंप बोले- ईरान के साथ जारी रहेगी बातचीत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में तीन घंटे से ज्यादा समय तक बंद कमरे में अहम बैठक हुई। बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से जोर देकर कहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी रहनी चाहिए।

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्प्लीटर बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।